RNI .NO. MPBIL / 2013/ 54381

संपादकः- डॉ. देवेन्द्र मालवीय

11 वर्ष

दैनिक

सद्भावना पाती

...प्राणियों में सद्भावना हो...

www.sadbhawnapaati.com Email: sadbhawnapaatinews@gmail.com इंदौर, शुक्रवार ●05 अप्रैल , 2024 वर्षः-11 अंक - 337 मूल्य -1 रु. कुल पृष्ठ - 8

'43' तक पहुंचा पारा, 'लू' की चपेट में देश के 6 राज्य

एमपी के 18 जिलों में बारिश की संभावना, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश के 6 राज्यों में लू चल रही है। इनमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। यहां का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने केरल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी रहने की बात कही है। इनमें जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। मौसम विभाग ने कहा कि 7 अप्रैल से मध्यप्रदेश के 18 और बिहार के 9 जिलों में बारिश हो सकती है। वहीं, झारखंड में 7 अप्रैल तक राज्य में लू का यलो अलर्ट जारी किया है। मध्यप्रदेश में अप्रैल में आंधी-बारिश का ट्रेंड है। पिछले 10 में से 7 साल बारिश हुई। इस बार भी ऐसा ही मौसम रहेगा। 7 अप्रैल से अगले 2 दिन प्रदेश के कई जिलों में आंधी-बारिश का दौर रहेगा। जबलपुर, भोपाल, शहडोल, रीवा समेत 18 जिलों में बारिश हो सकती है। आईएमडी भोपाल के अनुसार 5 अप्रैल से वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) ऐक्टिव हो रहा है। इसका असर 1-2 दिन के बाद प्रदेश में देखने को मिलेगा। खासकर पूर्वी हिस्से में बारिश, आंधी और बादल रहेंगे। झारखंड में तेज धूप के साथ अब हीटवेव का खतरा भी बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने इसे लेकर 7 अप्रैल तक राज्य में हीटवेव का यलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान प्रदेश के कई जिलों में तापमान 40 के पार जाने की पूरी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के दक्षिणी-पूर्वी भाग में गर्म हवा की स्थिति बन रही है। 5 अप्रैल को पूर्वी भाग में इसका असर देखने को मिल सकता है। 7 अप्रैल के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक, 8 और 9 अप्रैल को राज्य के कई जिलों में गर्जन के साथ बारिश की संभावना बन रही है।

चुनाव ड्यूटी को लेकर प्रदेश में शुरू हो गए हैं दांव-पेंच

- अब अतिथि शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाने कलेक्टरों को पत्र, संविदा कर्मियों पर पहले से रोक

भोपाल। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए पहले और दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के साथ अब मतदान की तैयारियों पर 13 लोकसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों और कलेक्टरों की टीम ने फोकस किया है। इसके लिए चुनावी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। इस बीच संविदा कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं लगाने के मुख्य चुनाव आयुक्त के निर्देश तथा अतिथि शिक्षकों व परीक्षा मूल्यांकन में तैनात शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाने को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग के अफसरों के आदेश कलेक्टरों तक पहुंच रहे हैं। इसके बाद अब पहले से ही चुनाव के लिए कर्मचारियों का संकट झेल रहे कलेक्टरों के समक्ष और भी दिक्कतें होना तय हो गई है। हालांकि चुनाव आयोग अतिथि शिक्षकों और आउटसोर्स कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी में लगाने से मना कर चुका है।

लोकसभा चुनाव से पहले नवनीत राणा को 'सुप्रीम' राहत

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा चुनावों से पहले अमरावती से सिटिंग सांसद और बीजेपी कैंडीडेट नवनीत राणा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। मामला नवनीत राणा के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र से जुड़ा है। जिसे हाई कोर्ट ने जाली बताते हुए रद्द कर दिया था और दो लाख का जुर्माना लगाया था। हाई कोर्ट के फैसले के बाद उनकी सांसदी खतरे में आ गई थी। दरअसल, नवनीत राणा महाराष्ट्र की अमरावती लोकसभा सीट से सांसद हैं। यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 2021 में बॉम्बे हाई कोर्ट में यह याचिका डाली गई कि नवनीत ने जाली दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ा और जीता। मामले में सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी माना कि नवनीत राणा ने जाली जाति प्रमाण पत्रों के बल पर चुनाव लड़ा था। इसलिए उनका जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया।

लव ट्रायंगल : डबल मर्डर और सुसाइड

सरफिरे आशिक ने एकतरफा प्यार में लड़की और उसके साथी युवक की गोली मारकर हत्या की, खुद ने भी किया सुसाइड

इंदौर। भंवरकुआं में गुरुवार दोपहर एक छात्र ने एकतरफा प्यार में लड़की और उसके रिश्तेदार युवक को गोली मार कर हत्या कर दी फिर कुछ दूर जाकर खुद ने भी सुसाइड कर लिया। पुलिस के मुताबिक घटना स्वामी नारायण मंदिर कैम्पस की है। लड़की स्नेहा जाट निवासी जूनी इंदौर और उसका रिश्तेदार दीपक जाट निवासी आगर मालवा मंदिर में दर्शन करने आए थे। एक अन्य लड़का अभिषेक यादव निवासी इंदौर पहले से मौजूद था, जो स्नेहा से एकतरफा प्यार करता था। दोनों को साथ देखकर लड़की और उसके दोस्त को गोली मार दी। फिर यहां से सामने भाग गया। वह घबराते हुए अरिहंत कॉलेज कैम्पस में पहुंचा और सिक्योरिटी गार्ड से पानी मांगा। उसे लगा कि दो लोगों को गोली मारने के बाद खुद भी नहीं बच पाएगा। इसी कारण से उसी पिस्टल से खुद को भी गोली मारकर खत्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक अभिषेक को स्नेहा और दीपक जाट की दोस्ती पसंद नहीं थी। वह स्नेहा से प्यार करता था लेकिन स्नेहा ने उसे मना कर दिया था। इसके चलते अभिषेक ने पूर्व में दोनों को हत्या की धमकी भी दी थी।

पुलिस पता कर रही पिस्टल कहां से आई- लोकसभा चुनाव के कारण पुलिस सभी लाइसेंसी हथियार जमा करा रही है। ऐसे में पुलिस यह भी पता कर रही है कि अभिषेक यादव के पास पिस्टल कहां से आई। पुलिस यह भी पता कर रही है कि पिस्टल अवैध तो नहीं है।

दिल्ली जल बोर्ड केस

पूर्व इंजीनियर और कॉन्ट्रेक्टर ईडी कोर्ट में हुए पेश

नई दिल्ली (एजेंसी)। जल बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में गुरुवार कोर्ट में पूर्व चीफ इंजीनियर और कॉन्ट्रेक्टर को पेश किया गया। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को आदेश दिया कि वो सभी आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी दे। जल बोर्ड के पूर्व चीफ इंजीनियर जगदीश आरोड़ा और कॉन्ट्रेक्टर अनिल अग्रवाल अभी ज्यूडिशियल कस्टडी में हैं। इनके अलावा एक अन्य आरोपी तेजिंदर सिंह को भी अदालत में पेश किया गया। चौथे आरोपी पूर्व जनरल मैनेजर डीके मित्तल ने अदालत में अर्जी दी कि उन्हें आज पेश होने से छूट दे दी जाए। कोर्ट ने 3 अप्रैल को ईडी की चार्जशीट पर ऐक्शन लेते हुए आरोपी देवेंदर मित्तल और तेजिंदर पाल सिंह को हाजिर होने का आदेश दिया था। इनके अलावा आरोपी जगदीश अरोड़ा और अनिल अग्रवाल को भी कोर्ट में पेश करने का नोटिस जारी किया गया।

कश्मीर की बेहतरी के लिए बदली धारा 370: सीएम

- संविधान बदलने के आरोपों पर विपक्ष को दिया जवाब
- सीएम ने कहा-लोगों की जिंदगी बदलना हमारा अभियान

भोपाल। केंद्र सरकार पर संविधान बदलने के आरोपों को लेकर सीएम डॉ. मोहन यादव ने विपक्ष को जवाब दिया है। सीएम ने बैतूल रवाना होने से पहले भोपाल में चर्चा में कहा- विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। संविधान में अगर 370 जैसी गलत धारा थी, उसे बदलना चाहिए तो उसे कश्मीर की बेहतरी के लिए बदलकर दिखाया। सीएम ने कहा- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे, लोगों की जिंदगी बदलने का अभियान चला रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। किसान, युवा, गरीब मजदूर सबकी जिंदगी बदलना, उनके जीवन में खुशहाली लाने की दिशा में नरेंद्र मोदी की सरकार काम कर रही है। सीएम ने कहा- राहुल गांधी अपने अंदर झांक कर देखें। संविधान बदलने का परिणाम ही रहा कि 3 तलाक जैसे निर्णय को कांग्रेस ने बदल दिया। कांग्रेस ने आपातकाल जैसे खराब समय में जिस प्रकार से ज्यूडिशियरी के साथ छेड़छाड़ की थी, उसका भी लंबा इतिहास है।

बीजेपी सांसद प्रज्ञा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

भोपाल। महाराष्ट्र के मालेगांव बम धमाके को लेकर मुंबई की एक विशेष अदालत ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई है। भोपाल की भाजपा सांसद प्रज्ञा इस मामले में आरोपी हैं और उनकी लगातार अनुपस्थिति से अदालत की सुनवाई में परेशानी हो रही है। विशेष अदालत ने एनआईए से भाजपा सांसद के स्वास्थ्य को लेकर रिपोर्ट भी मांगी है और 8 अप्रैल तक रिपोर्ट पेश करने का समय दिया है। भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने वकील के माध्यम से स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देकर पेशी से छूट मांगी थी। विशेष न्यायाधीश एके लाहोटी की अदालत में बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान भाजपा सांसद के वकील ने फिर से छूट की मांग की। वकील ने दावा किया कि प्रज्ञा ठाकुर सर्वाइकल-स्पॉन्डिलाइटिस और माइग्रेन से ग्रस्त हैं। आवेदन में कहा गया है कि उनकी शारीरिक स्थिति नियंत्रण से बाहर है, वह डॉक्टरों की सलाह पर भोपाल में अपने घर पर इलाज करा रही हैं।

आरजीपीवी घोटाला

फरार कुलगुरु को ढूढ़ने पर 3 हजार का ईनाम घोषित

- वीसी समेत 3 के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी

भोपाल। आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में हुए घोटाले को लेकर पुलिस ने जांच में तेजी की है। पुलिस कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर सुनील कुमार की तलाश कर रही है। आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर 3 हजार रुपए का ईनाम घोषित किया गया है। लुकआउट नोटिस दिल्ली से जारी कराया गया है। तत्कालीन वीसी सुनील कुमार गुप्ता के अलावा, तत्कालीन रजिस्ट्रार राकेश सिंह राजपूत और तत्कालीन वित्त नियंत्रक ऋषिकेश वर्मा के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। सभी के खिलाफ डीसीपी जोन 04 सुंदर सिंह कनेस ने 3-3 हजार के इनाम का ऐलान भी किया है। लगभग एक महीने पहले, 3 मार्च को सीएम मोहन यादव के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है।

भाजपा में आए गौरव वल्लभ और अनिल शर्मा

एक दिन में ही गिरे कांग्रेस के 3 महत्वपूर्ण विकेट

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद प्रोफेसर गौरव वल्लभ अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान से वल्लभ का पलायन कांग्रेस के लिए बड़े झटके के तौर पर माना जा रहा है उन्होंने कांग्रेस पर दिशाहीन पार्टी होने के आरोप लगाए थे। वल्लभ कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता भी थे। वल्लभ के साथ बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने भी भाजपा की सदस्यता ली। खास बात है कि महज दो दिनों के भीतर ही कांग्रेस को तीन राज्यों में तीन बड़े झटके लगे हैं। एक ओर जहां राजस्थान से आने वाले वल्लभ ने और बिहार कांग्रेस के दिग्गज शर्मा ने भाजपा का दामन थामा। वहीं, पार्टी से तनातनी के बीच महाराष्ट्र के नेता संजय निरुपम ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना में शामिल होने की तैयारी में हैं। वल्लभ ने लिखा, पार्टी आज जिस प्रकार से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है, उससे मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा हूं। मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं और ना ही सुबह-शाम देश के वेल्थ क्रिएटर को गाली दे सकता हूं। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों व प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहा हूं। निरूपम मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से महाविकास अघाड़ी के अमोल कीर्तिकार के उम्मीदवार बनाए जाने से नाराज थे। वह लगातार उन्हें खिचड़ी चोर बता रहे थे। उन्होंने कहा था कि उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस इस बात पर संज्ञान लेगी। साथ ही उन्होंने भी कांग्रेस को दिशाहीन करार दे दिया था।

नहीं दिखे मुस्लिम लीग के झंडे राहुल गांधी के रोड शो पर बवाल

- वायनाड में स्मृति ईरानी हुई हमलावर, लेफ्ट ने भी राहुल को घेरा

वायनाड़ (एजेंसी)। लोकसभा चुनाव से पहले मुस्लिम लीग के झंडे को लेकर सियासत शुरू हो गई है। वायनाड से पर्चा दाखिल करने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रोड शो किया था। इस रोड शो के दौरान मुस्लिम लीग का झंडा नदारद दिखा।

अब मुस्लिम लीग के झंडे को लेकर वामपंथ और दक्षिणपंथ दोनों ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह पार्टी की सहयोगी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) से शर्मिंदा हैं, वायनाड जिले में उनके रोड शो के दौरान मुस्लिम लीग का झंडा शामिल नहीं किया गया था। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि अगर उन्हें आईयूएमएल से शर्म आती है, तो उन्हें उनका समर्थन अस्वीकार कर देना चाहिए।

केजरीवाल के दिल्ली जल बोर्ड घोटाले सा मामला मध्यप्रदेश में भी

क्या ईडी लेगा निशाने पर ?

गौरव चतुर्वेदी

सदभावना पाती 05 अप्रैल 2024। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार इन दिनों एक तथाकथित शराब घोटाले के मामले में जेल में है। इसी के साथ ही ईडी दिल्ली जल बोर्ड में अनियमितताओं से जुड़े एक मामले को लेकर तल्ख तेवर अपनाए हुए है। जांच एजेंसी ने जिस तरह के गड़बड़ियों संबधी तथ्य इस मामले में पाए हैं ठीक वैसी ही गड़बड़ी मध्यप्रदेश में भी एक टेंडर में की गई है। हालांकि मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। इस मामले का दिलचस्प पहलू मध्यप्रदेश के बड़े अधिकारियों का इस घोटाले में शामिल होना रहा। सूत्रों के अनुसार इस मामले में शिवराज सरकार भी शामिल रही।

कैसा है दिल्ली का मामला – आप को दोहरा झटका- आप के चुनावी फंड में दिया गया जल बोर्ड घोटाले का पैसा : ईडी

ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) में अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत में आरोपपत्र दायर कर दिया। आठ हजार पेज का आरोपपत्र मनी लांड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत में

दायर किया गया। ईडी ने आरोपितों पर पीएमएलए के तहत मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी है। अदालत ने आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के लिए एक अप्रैल की तारीख तय की है। ईडी ने आरोप लगाया है कि जल बोर्ड द्वारा जारी एक अनुबंध में भ्रष्टाचार से मिला पैसा आम आदमी पार्टी को चुनावी हीं फंड के रूप में दिया गया था।

आरोपपत्र में चार व्यक्तियों और एक कंपनी को आरोपित बनाया गया है। इनमें डीजेबी के पूर्व मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोड़ा, ठेकेदार अनिल कुमार अग्रवाल, एनबीसीसी के पूर्व महाप्रबंधक डीके मित्तल, तेजिंदर सिंह और एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड शामिल हैं। गई ईडी ने मामले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी बुलाया था, लेकिन वह पेश नहीं हुए। इसके बाद एजेंसी ने केजरीवाल को 21 मार्च को आबकारी नीति घोटाला से जुड़े मामले में गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले ईडी ने फरवरी में जांच के तहत केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार, आप के राज्यसभा सदस्य और कोषाध्यक्ष एनडी गुप्ता, पूर्व डीजेबी सदस्य शलभ कुमार, चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज मंगल और कुछ अन्य के परिसरों पर छापेमारी की थी।

देखना है जिस आधार पर ईडी दिल्ली सरकार के खिलाफ नोटिस जारी कर रही है। उसी तरह के मध्यप्रदेश के इस मामले में ईडी कोई कार्रवाई करेगा ?

सीबीआई की एफआईआर है ईडी के लिए आधार

ईडी के मामले का आधार सीबीआई द्वारा दर्ज की एफआईआर है। इसमें अरोड़ा पर एनकेजी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 38 करोड़ रुपये का अनुबंध देने का आरोप लगाया गया है। कंपनी तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करती थी। इसके बावजूद उसे अनुबंध दिया गया। ईडी ने मामले में अरोड़ा और अग्रवाल को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था।

यह है मध्यप्रदेश का मामला

गौरतलब है कि खबर नेशन ने पूर्व में इंदौर में बन रहे नये जिला न्यायालय परिसर में हुई गड़बड़ियों को लेकर मामला प्रकाशित किया था। जिला न्यायालय के भवन निर्माण कर रही आर्कन पावर इंफ्रा इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज लगाकर प्रथम निविदाकार के तौर पर काम हासिल किया था। इन गड़बड़ियों को लेकर द्वितीय स्थान पर रहे निविदाकार कल्याण टोल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा लिमिटेड ने मध्यप्रदेश के लोक निर्माण विभाग के तत्कालीन मंत्री, विभागीय प्रमुख सचिव, को शिकायत की थी। शिकायत के दिन ही विभागीय प्रमुख सचिव ने अपने मातहत अफसरों को आर्कन पावर इंफ्रा इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध कराए जाने के निर्देश दे दिए। शिकायत किए जाने और अनुबंध के बीच पंद्रह दिन का समय अंतराल रहा लेकिन शिकायत पर गौर ही नहीं किया गया। बताया जा रहा है उस दौरान मध्यप्रदेश सरकार गुजरात लॉबी के दबाव में कार्य कर रही थी जिसके चलते शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया। गौरतलब है कि आर्कन पॉवर इंफ्रा इंडियन प्राइवेट लिमिटेड गुजरात बेस्ड कंपनी है। जिसे लेकर कल्याण टोल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की शरण में चली गई।

प्रदेश पाती

दैनिक सद्भावना पाती

इंदौर, शुक्रवार 05 अप्रैल, 2024

संक्षिप्त समाचार

नहरों के माध्यम से अंतिम छोर के खेतों की सिंचाई के लिये पानी पहुँचाएं

हरदा (निप्र)। कलेक्टर श्री आदित्य सिंह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ दौरा कर नहरों के माध्यम से मूंग की फसल की सिंचाई के लिये की गई व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिये कि अंतिम छोर पर स्थित खेतों तक नहर का पानी पहुँचाया जाए। इस दौरान कलेक्टर श्री सिंह ने ग्राम उंद्राकच्छ, कुकरावद, नकवाड़ा, रहटाखुर्द, मरदानपुर, जतराखेड़ी, रोलगांव का दौरा कर नहर से आ रहे पानी के स्तर को चैक किया। निरीक्षण के दौरान उन्होने निर्देश दिये कि नहर से सिंचाई के लिये अवैध रूप से पानी लेने वाले किसानों को रोका जाये। उन्होने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जिन किसानों को नहर से पानी लिफ्ट करने के लिये जल संसाधन विभाग ने अनुमति दी है, वे विधिवत विद्युत कनेक्शन लेकर ही पम्प का संचालन करें। इस दौरान कार्यपालन यंत्री जल संसाधन श्री डी.के. सिंह सहित विभाग के अन्य अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित थे।

शासकीय महाद्यिालय शाहगंज में नैक क्राइटेरिया-7 के तहत प्रदर्शनी लगाई

सीहोर (निप्र)। शासकीय महाद्यिालय शाहगंज में गत दिवस नैक क्राइटेरिया-7 के अन्तर्गत बीएससी प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों द्वारा भौतिक शास्त्र विषय के वर्किंग प्रोजक्टस की प्रदर्शनी लगाई गई। यह कार्यक्रम महाद्यिालय के प्रभारी प्राचार्य के संरक्षण में किया गया। प्रदर्शनी में महाद्यिालय के समस्त स्टॉफ एवं विद्यार्थियों द्वारा सहभागिता की गई।

नई गाइडलाइन विभागीय वेबसाइट पर एक अप्रैल से उपलब्ध रहेगी

सीहोर (निप्र)। मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्थाई संपत्ति के बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए बनाए गए नियमों एवं बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार जिले की गाइडलाइन केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड के अनुमोदन के बाद कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह द्वारा एक अप्रैल 2024 से प्रभावशील करने के आदेश जारी किए गए हैं। यह गाईड लाईन एक अप्रैल 2024 प्रभावशील होकर विभागीय वेबसाइट https://www.mpigr.gov.in/ पर उपलब्ध होगी ।

पेयजल शिकायतों के निराकरण के लिए लिए कंट्रोल रूम स्थापित

सीहोर (निप्र)। आगामी ग्रीष्म काल को दृष्टिगत रखते हुए पेयजल संबंधी शिकायतों के निराकरण तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कंट्रोल रू म स्थापित किए गए है। खंड सीहोर के लिए कंट्रोल रूम प्रभारी फिटर ग्रेड -3 श्री मेहबूब खान , उपखंड सीहोर के लिए कंट्रोल रूम प्रभारी हैण्डपम्प तकनीशियन÷श्री गणेश सोनी , उपखण्ड भैरूंदा के लिए कंट्रोल रूम प्रभारी सहायक ग्रेड-03 श्री सचिन ठाकुर , उपखंड आष्टा के लिए कंट्रोल रूम प्रभारी सहायक ग्रेड -03 श्री एस. से तिवारी , बुधनी के लिए कंट्रोल रूम प्रभारी स्टोर क्लर्क राजकुमारी सोलंकी को नियुक्त किया गया है।

सड़क का जायजा

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री बुद्धेश कुमार वैद्य ने आज भ्रमण के दौरान ग्राम पांझ पहुंच मार्ग निर्माण सड़क के कार्यो की गुणवत्ता का परीक्षण किया। उन्होंने सड़क के दोनो और शोल्डर ठीक कराने के निर्देश दिए है। उन्होंने सड़क निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार से गुणवत्ता में कोई लापरवाही ना बरती जाए का विशेष ध्यान देने के निर्देश लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री एलएस यादव को दिए है। निरीक्षण के दौरान विभाग के एसडीओ श्री रविप्रकाश चिड़ार ने सड़क मार्ग की ड्राइंग और पुल-पुलियों से बिन्दुवार अवगत कराया है।

भाजपा कार्यकर्ताओं के जोश और होश से कांग्रेस बेहोश हो गई - ज्योतिरादित्य सिंधिया

सिंधिया ने शिवपुरी जिले में मंडल कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया

शिवपुरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस लोकसभा चुनाव में 400 से अधिक लोकसभा सीटों का लक्ष्य निर्धारित किया है। पार्टी ने नारा भी दिया है, अबकी बार 400 पार। आप सभी कार्यकर्ता 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऐतिहासिक मतों से पार्टी प्रत्याशी को जिताएं। हमें जब तक नहीं बैठना है तब तक हमें 400 पार का लक्ष्य पूरा न कर लें। भाजपा कार्यकर्ताओं के जोश और होश से कांग्रेस पार्टी बेहोश हो गई। यह बात केंद्रीय मंत्री व गुना लोकसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी जिले के खनियाधाना में मंडल कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कही।

अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा का नारा लगाया– सिंधिया ने पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेई के अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा का नारा लगाते हुए हर बूथ में 370 नए मतदाताओं को पार्टी से जोड़कर भाजपा को ऐतिहासिक विजय दिलाने का आह्वान किया। सिंधिया ने भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने की रणनीति बताते हुए कहा कि गुना-शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक जीत के लिए कार्यकर्ता अपने अंदर जीत के लिए उत्साह के साथ कार्य करें। बैठक में खनियांधाना, बामौरकलां, मायापुर मंडल के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कलेक्टर सिंह ने महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा की

आंगनवाड़ी केन्द्रों को आकर्षक व सर्व सुविधायुक्त बनाया जाएगा

हरदा (निप्र)। कलेक्टर श्री आदित्य सिंह ने मंगलवार को महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की बैठक लेकर विभागीय योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में उन्होने कहा कि जिले के आंगनवाड़ी केन्द्रों की रंगाई पुताई व पेंटिंग कराकर आकर्षक बनाया जाए और आंगनवाड़ी भवन की दीवारों पर महिलाओं और बच्चों के लिये संचालित योजनाओं की जानकारी तथा आंगनवाड़ी में वितरित होने वाले पोषण आहार का मेनू, पेन्ट कर लिखवाया जाए। आंगनवाड़ी केन्द्रों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त समय में युवा छात्राओं को उच्च शिक्षण के लिये कोचिंग देने की व्यवस्था भी की जाए।

इसके लिये जिला प्रशासन हर संभव मदद उपलब्ध करायेगा। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री संजय त्रिपाठी सहित विभाग की परियोजना अधिकारी व सुपरवाइजर मौजूद थी। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री त्रिपाठी ने बताया कि जिले में 699 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 424 विभागीय सरकारी भवन में संचालित है। अन्य शासकीय भवनों में 145 तथा किराये के भवनों में 130 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। जिले में 40 आंगनवाड़ी भवन निर्माणाधीन है।

कलेक्टर श्री सिंह ने आंगनवाड़ी केन्द्रों में आने वाली महिलाओं के लिये अलग से शौचालय की व्यवस्था कराने के निर्देश दिये। उन्होने पुराने खण्डहर हो चुके आंगनवाड़ी भवनों को गिराकर नये आंगनवाड़ी भवन निर्माण के प्रस्ताव शासन को भिजवाने के लिये भी कहा। उन्होने घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की मदद के लिये संचालित विधिक सहायता, पुलिस सहायता, चिकित्सा सहायता व आश्रय सहायता से संबंधित योजनाओं की जानकारी देने के लिये विभागीय सुपरवाईजर्स को निर्देश दिये। उन्होने महिलाओं के लिये संचालित निःशुल्क विधिक सहायता योजना के प्रचार-प्रसार पर विशेष ध्यान देने के लिये कहा ताकि अधिकाधिक पीड़ित महिलाएं इन योजनाओं का लाभ ले सकें। कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में निर्देश दिये कि बच्चियां स्कूल की पढ़ाई बीच में न छोड़ें, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए तथा शिक्षा विभाग के साथ समन्वय बनाकर इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जाए।

कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में कहा कि पोषण पुनर्वास केन्द्रों में भर्ती कुपोषित बच्चों के मनोरंजन के लिये खेल खिलौने की व्यवस्था तो रहती है। अब इन केन्द्रों में भर्ती कुपोषित बच्चों की माताओं के मनोरंजन के लिये संसाधन उपलब्ध कराने के लिये जिला प्रशासन हर संभव मदद देगा। उन्होने कहा कि बच्चों की माताओं की सुविधा के लिये इन केन्द्रों में सिलाई मशीन या इस तरह के अन्य संसाधन उपलब्ध कराये जायें ताकि महिलाएं अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकें। बैठक में उन्होने लाड़ली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सहित अन्य विभागीय योजनाओं तथा वन स्टॉप सेंटर की गतिविधियों की समीक्षा भी की।

अभ्यर्थी सहित 5 व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी कक्ष में कर सकेंगे प्रवेश

सीहोर (निप्र)। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया है कि नामांकन भरने पहुंचे अभ्यर्थी के साथ 4 व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। 100 मीटर के अंदर केवल तीन वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। नामांकन भरने की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी और दोपहर 3 बजे तक चलेगी। 3 बजे के उपरांत कक्ष में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने अथवा दस्तावेज लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थियों को सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे नामांकन फार्म जमानत राशि का प्रमाण, प्रारूप-ए एवं बी, शपथ पत्र आदि के साथ आरओकक्ष में लेकर आना होगा। यदि अभ्यर्थी उसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है, जहां से वह चुनाव लड़ रहा है तो अभ्यर्थी को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की प्रति या निर्वाचक नामावली से संबंधित भाग की प्रमाणित प्रति दाखिल करनी होगी।एक अभ्यर्थी एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। एक साथ या पृथक से जमा किया जा सकता है। नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्रॉफी भी कराई जाएगी।

मतदाता जागरूकता अभियान अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन जारी

ग्रामीण क्षेत्रों में दीवार लेखन के माध्यम से भी मतदाताओं को किया जा रहा जागरूक

विदिशा (निप्र)। लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत तीसरे चरण में 7 मई को विदिशा जिले की पांचो विधानसभाओं के 1341 मतदान केन्द्रों पर मतदान होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बुद्धेश कुमार वैद्य के मार्गदर्शन में विदिशा जिला सर्वाधिक मतदान वाला जिला बने इस हेतु विभिन्न स्तर पर जिले के नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता गतिविधियों का आयोजन जारी है। इसी क्रम में आज जिले की ग्राम पंचायत कुल्हार में रंगोली बनाकर मतदाताओं को मतदान के लिए अभिप्रेरित किया है। साथ ही साथ ग्राम पंचायत आटस के हाट बाजार में खरीदारी करने आए मतदाताओं को रैली के माध्यम से जागरूक किया गया है और उन्हें मतदान दिवस पर नियत किए गए मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान अवश्य करें का संदेश दिया है। ग्राम पंचायत तिलातिली और सतपाड़ाहाट में भी इसी तरह स्वीप गतिविधियों का आयोजन कर मतदाताओं को जागरूक किया गया। इसके अलावा ग्राम पंचायत खेजड़ा सुल्तान में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई तथा शाला बमोरी ग्राम में ग्रामीण मतदाताओं को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई गई है। इसके अलावा ग्राम पंचायत सौराई, दुपारिया और पड़रायत समेत अन्य ग्रामों में दीवार लेखन के माध्यम से मतदाता जागरूकता के संदेशों का प्रसारण कार्य जारी है। ग्रामीण क्षेत्र की दीवारों पर विभिन्न प्रकार के स्लोगन जैसे अपने मतदान पर गर्व कीजिये, वोट दीजिए वोट दीजिए तथा भारत भाग्य विधाता हूं, अब तो मैं मतदाता हूं के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है।

बिजली चोरी की रोकथाम के लिए पारितोषिक योजना बिजली चोरी की सूचना देने वालों को मिला 2 लाख रुपये का पारितोषिक

सीहोर (निप्र)। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली चोरी की गुप्त सूचना देने वालों को अब 2 लाख रुपये का पारितोषिक दिया गया है। योजना में वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में लगभग 55 प्रकरणों में सूचना प्राप्त होने के उपरांत, 27 प्रकरणों में, अवैध बिजली की चोरी पाये जाने पर, बिल की राशि रूपये 20 लाख की शत-प्रतिशत वसूली होने पर, लगभग 2 लाख रूपये की पारितोषिक की राशि संबंधित सूचनाकर्ता के बैंक खाते में सीधे जमा की गयी है। कंपनी द्वारा विद्युत की चोरी के प्रभावी रोकथाम एवं विद्युत के अवैध उपयोग को रोकने के लिए यह योजना चलाई गई है। योजनांतर्गत कोई भी व्यक्ति बिजली के अवैध उपयोग के संबंध में सूचना कंपनी मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय में मुख्य महाप्रबंधक, संचा. संधा/शहर वृत्त कार्यालय के महाप्रबंधकों को लिखित अथवा मोबाईल पर दे सकता है। कंपनी की वेबसाईट portal.pmcz.in पर ऑनलाईन सूचना देने की व्यवस्था की गई है। सफल सूचनाकर्ता को अथवा उपभोक्ता को विद्युत चोरी की क्षतिपूर्ति की पूर्ण राशि जमा होने पर, बिल की राशि के दस प्रतिशत की राशि को पारितोषिक राशि के रूप में दिये जाने की योजना जनवरी 2019 से प्रचलन में है। योजना के अंतर्गत सूचनाकर्ता के संबंध में जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखते हुए, कंपनी मुख्यालय से प्रोत्साहन की राशि सीधे संबंधित सूचनाकर्ता के बैंक के खाते में हस्तांतरित की जाती है। इस योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय, वृत्त स्तर के अधिकारियों को जो शिकायतें प्राप्त होती है, शिकायतों पर तत्परता से कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के लिए कंपनी द्वारा सतत रूप से निगरानी रखी जाती है। फर्म, एजेंसी, संगठन भी सूचनाकर्ता हो सकते है, जिन्हें कंपनी मुख्यालय में पदस्थ नोडल अधिकारी के माध्यम से पंजीकरण कराना आवश्यक है।

पोर्टल अथवा उपाय एप पर देनी होगी सूचना

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इनाम योजना सूचनाकर्ता को निर्धारित शर्तों के अधीन पारितोषिक देने का प्रावधान है। सूचना के आधार पर राशि वसूली होने पर सफल सूचनाकर्ता को 10 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा। इस राशि की अधिकतम सीमा नहीं है। सूचनाकर्ता को प्रोत्साहन राशि कंपनी मुख्यालय द्वारा सीधे सूचनाकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी। प्रकरण बनाने एवं राशि वसूली करने वाले विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी ढाई प्रतिशत राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी।

बंदियों के अधिकारों का संरक्षण हमारा कर्तव्य है

सीहोर (निप्र)। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री सतीश चंद्र शर्मा द्वारा जिला जेल का निरीक्षण किया गया। जिसमें पाकशाला, जेल डिस्पेंसरी, स्टोर रूम, महिला सेल तथा अन्य बंदियों के बैरक आदि का निरीक्षण किया गया। महिला सेल के निरीक्षण के दौरान महिला बंदियों के साथ निरूद्ध बच्चों के पोषण, भोजन, स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं तथा उनके प्रकरणों की प्रगति के सम्बंध में विस्तार से जानकारी ली गई। उनके द्वारा बंदियों की समस्याओं को सुना गया तथा त्वरित निराकरण के लिए सम्बंधितों को निर्देशित किया गया। पाकशाला के निरीक्षण के दौरान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भोजन की गुणवत्ता जानने के लिए उसे चख गया। साथ ही स्टोर रूम निरीक्षण के दौरान गेहूं , चावल, दाल आदि सामग्री की गुणवत्ता भी देखी गई। निरीक्षण के साथ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन भी किया गया। जिसमें प्रधान जिला न्यायाधीश श्री सतीश चंद्र शर्मा द्वारा बंदियों को बताया गया. कि आपके बचाव के लिए गुणवत्तापूर्ण पैरवी के लिए दृष्टिगत रखते हुए लीगल एड डिफेंस काउंसिल्स की नियुक्ति की गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बंदियों के अधिकारों का संरक्षक है एवं बंदियों के अधिकारों का संरक्षण हमारा कर्तव्य है। किसी भी बंदी को जेल में निरोध के दौरान अधिवक्ता नियुक्ति, प्रकरण की अद्यतन जानकारी एवं जेल से सम्बंधित कोई भी समस्या होने पर वह तत्काल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित कर सकते है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री मुकेश कुमार दांगी द्वारा जेल में निरूद्ध बंदियों को उनके अधिकार, लीगल एड डिफेंस काउंसिल योजना, प्ली बारगेनिंग, निःशुल्क विधिक सहायता योजना, म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना एवं नालसा, सालसा की योजनाओं, शासन की अन्य योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। निरीक्षण के दौरान जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री जीशान खान, जेल अधीक्षक सुश्री प्रतिभा पटेल, जेल उप अधीक्षक श्रीमती ज्योति तिवारी एवं लीगल एड डिफेंस काउंसिल्स श्री आसिफ खान, एवं बंदीगण उपस्थित रहें।

रायसेन में नगर पालिका द्वारा निकाली गई मतदता जागरूकता रैली, नैतिक मतदान की ली शपथ

रायसेन (निप्र)। लोकसभ आम निर्वाचन-2024 में अधिकाधिक मतदान हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अरविंद दुबे के निर्देशानुसार चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान के तहत बुधवार को नगर पालिका रायसेन द्वारा शास.स्वमा विवेकानंद महाविद्यालय से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रायसेन एसडीएम श्री पीसी शाक्य द्वारा सभी को लोकसभा निर्वाचन में बिना किसी भय, दबाव या लालच के स्वविवेक से नैतिक मतदान करने की शपथ भी दिलाई गई। रैली में सीएमओ रायसेन सुश्री सुरेखा जाटव, जनशिक्षक श्री सूर्यप्रकाशन सक्सेना सहित अन्य अधिकारी और छात्र-छात्राएं शामिल हुए।

ग्रीष्म ऋतु में पेयजल व्यवस्था के लिये हर संभव इंतजाम किये जायें

कलेक्टर सिंह ने जनपद के सीईओ, सीएमओ व पीएचई के अधिकारियों को दिये निर्देश

हरदा (निप्र)। कलेक्टर श्री आदित्य सिंह ने मंगलवार को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक में निर्देश दिये कि ग्रीष्म ऋतु में जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिये हर संभव प्रयास किये जायें। कलेक्ट्रेट में मंगलवार को आयोजित बैठक में जिला पंचायत के सीईओ श्री रोहित सिसोनिया के अलावा जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी भी मौजूद थे।

बैठक में उन्होने निर्देश दिये कि गांवों में हेण्डपम्प खराब होने की शिकायत प्राप्त होते ही त्वरित कार्यवाही कर हेण्डपम्प को सुधारने की व्यवस्था की जाए। उन्होने निर्देश दिये कि विकासखण्ड व जिला स्तर पर पेयजल व्यवस्था के लिये कंट्रोल रूम स्थापित किये जायें, जिनमें पंजी संधारित कर प्राप्त शिकायतों को दर्ज करें और उनका निराकरण करें। कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में जल जीवन मिशन के तहत संचालित पेयजल योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में कार्यपालन यंत्री श्री पवनसुत गुप्ता ने बताया कि मिशन की 166 पेयजल योजनाएं पूर्ण हो चुकी है।

नगरीय व ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल समस्या का अग्रिम आंकलन करें

कलेक्टर श्री सिंह ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे ग्रामीण क्षेत्रों के लिये जनपद के सीईओ के साथ समन्वय बनाकर संयुक्त सर्वे करें तथा पेयजल समस्या से ग्रस्त ग्राम चिन्हित करें और वहां की पेयजल समस्याओं का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता से करें। उन्होने कहा कि पीएचई के अधिकारी नगरीय व ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल समस्या का अग्रिम आंकलन करें। उन्होने जनपद पंचायत के सीईओ को निर्देश दिये कि पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायक से प्रतिदिन गांवों की पेयजल समस्या की जानकारी लेते रहें और उनके निराकरण की कार्यवाही भी करते रहें। उन्होने सभी एसडीएम को निर्देश दिये कि वे अपने क्षेत्र के जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी और पीएचई के अधिकारियों की संयुक्त बैठक लेकर पेयजल समस्या के निराकरण के लिये मॉनिटरिंग करें। बैठक में जिला पंचायत के सीईओ श्री सिसोनिया ने सभी सीएमओ व सीईओ जनपद से कहा कि लोकसभा निर्वाचन के मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं के लिये पानी व छांव की व्यवस्था की जाए।

दैनिक
सद्भावना पाती

इंदौर पाती

...प्राणियों में सद्भावना हो...

इंदौर, शुक्रवार 05 अप्रैल, 2024

साइबर सिक्योरिटी के गुर सीखेंगे इंदौर के बिजली अधिकारी

इंदौर। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के तीन अधिकारी मुंबई और नई दिल्ली में साइबर सिक्योरिटी की उच्च स्तरीय ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे। इस ट्रेनिंग में साइबर अटैक से बचाव के तरीके भी प्रमुख रूप से बताए जाएंगे।मुख्य महाप्रबंधक रिंकेश कुमार वैश्य ने बताया कि साइबर सुरक्षा और कौशल विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके तहत न केवल स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर के ट्रेनिंग सत्र में भी कंपनी के अधिकारियों को भेजकर उच्च प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसी क्रम में कंपनी के दो अधिकारी आशीष तिवारी और आदित्य प्रताप सिंह ठाकुर नवी मुंबई के पास महोपाड़ा में 5 से 14 अप्रैल तक ट्रेनिंग लेंगे। यहां नेशनल टेक्निकल रिसर्च आर्गेनाइजेशन से संबंद्ध संस्था साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग सह ऑपरेशनल एक्सरसाइज कार्यक्रम का दस दिनी आयोजन कर रही है।मुख्य महाप्रबंधक वैश्य के अनुसार, कंपनी के उपमहाप्रबंधक सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सिक्योरिटी विंग प्रभारी गौतम कोचर भी नई दिल्ली के मानेकशा सेंटर में 13-14 अप्रैल को साइबर सिक्योरिटी को लेकर रणनीतिक अभ्यास पर ट्रेनिंग लेंगे। मुख्य महाप्रबंधक ने बताया कि कंपनी का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग के साथ ही साइबर सिक्योरिटी पुख्ता करना एवं उपभोक्ताओं को निर्बाध और समय पर सेवाएं उपलब्ध कराना है।

फर्जी मार्कशीटः कोचिंग सेंटर संचालक गिरफ्तार

इंदौर। छात्र-छात्राओं की फर्जी मार्कशीट बनाने के मामले में पुलिस ने कोचिंग सेंटर संचालक को गिरफ्तार किया है। आरोपित ने कई शिक्षण संस्थानों की 10 से ज्यादा मार्कशीट बनवाई थी। आरोपित गिरोह के मास्टर माइंड से जुड़ा है।विजय नगर थाना पुलिस के मुताबिक आरोपित शिवशंकर तिवारी निवासी कृष्णबाग कालोनी है। आरोपित कृष्णबाग कालोनी के समीप ही कोचिंग सेंटर संचालित करता है। कोचिंग पर आने वाले छात्र-छात्राओं को जाली मार्कशीट बना कर देता था। पूछताछ में बताया वह गिरोह के मास्टरमाइंड दिनेश तिरोले से सबसे पहले संपर्क में आया था। उसने तिरोले और भवानी नगर के राज शर्मा (स्कूल संचालक) के माध्यम से 10 से ज्यादा मार्कशीट बनवाई है। कुछ मार्कशीट माध्यमिक बोर्ड दिल्ली और कुछ अन्य बोर्ड की है। एक मार्कशीट के बदले 12 से 15 हजार रुपये लेता था। राज और दिनेश को सात हजार रुपये ही देता था।

कंपोस्टिंग प्लांट सीटीपीटी व्यवस्था में आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए

इंदौर। निगमायुक्त लगातार मैदानी दौरे कर रहे हैं। अभी कई जगह सड़कों या खाली भूखंडों पर कचरा पड़ा मिलता है। लिहाजा उन्होंने निर्देश दिए कि इस तरह कचरा फेंकने वालों के खिलाफ भारी जुर्माना आरोपित किया जाए। आज सुबह मेघदूत गार्डन भी पहुंचे और सुबह की सैर और योगा करने वालों से साफ-सफाई के साथ गार्डन की अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। वहीं भानगढ़ रोड स्थित जीटीएस प्लांट का निरीक्षण करते वक्त रैम्प को ठीक करने और आवश्यक व्यवस्थाएं भी दुरुस्त करने के निर्देश आयुक्त शिवम वर्मा ने दिए। आज वे झोन क्र. 5 की सफाई व्यवस्था देखने निकले।आयुक्त श्री वर्मा कल विजयनगर चौराहा, सयाजी चौराहा, मेघदूत गार्डन, बापट चौराहा, न्याय नगर, सुखलिया चौराहा, चंद्रगुप्त मौर्य चौराहा, भानगढ़ रोड एवं अन्य आसपास के क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। आयुक्त श्री शिवम वर्मा द्वारा सर्वप्रथम मेघदूत गार्डन का अवलोकन किया गया, मेघदूत गार्डन में आने वाले मॉर्निंग वॉकर और योगा करने वालो से गार्डन की सफाई व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की गई। आयुक्त द्वारा मेघदूत गार्डन के निरीक्षण के दौरान गार्डन में बनाए गए कंपोस्टिंग प्लांट सीटीपीटी व्यवस्था व्यवस्था में आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही मेघदूत गार्डन में स्थित नर्सरी का भी अवलोकन किया गया नर्सरी में सुधार और अच्छे पौधे लगाने के संबंध में निर्देश दिए गए। आयुक्त श्री वर्मा द्वारा मेघदूत गार्डन पर प्लास्टिक फ्री मार्केट का भी अवलोकन किया गया। एनजीओ संस्था एचएमएस के सनप्रीत सिंह ने बताया कि किस प्रकार से मेघदूत गार्डन के बाहर चौपाटी मार्केट में किसी भी प्रकार का अमानक प्रतिबंधित पॉलिथीन एवं डिस्पोजल का उपयोग नहीं किया जाता है। आयुक्त श्री वर्मा द्वारा जोन क्रमांक 5 वार्ड क्रमांक 33 के अंतर्गत पी सेक्टर में रहवासियों से डोर टू डोर कचरा संग्रहण के संबंध में चर्चा की गई, कचरा संग्रहण के लिए वाहन वहां समय पर आता है या नहीं और 6 बिन सेग्रीगेशन के संबंध में रहवासियों से चर्चा की गई। रहवासी द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा कचरा पृथक पृथक तो रखा ही जाता है साथ ही हम कंपोस्टिंग भी किया जाता है इसका अवलोकन भी आयुक्त द्वारा किया गया और अन्य नागरिकों को भी रहवासी द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए प्रेरित करने के लिए कहा गया। इसके पश्चात आयुक्त द्वारा न्याय नगर में कचरा संग्रहण कार्य का अवलोकन करते हुए रहवासियों से चर्चा की गई।

70 से ज्यादा आदर्श मतदान केंद्र बनेंगे

इंदौर। मई मे होने वाले लोकसभा चुनाव के चलते नगर निगम का अमला अब मतदान केंद्रों को चकाचक करने में जुटा है। इस बार 1760 मतदान केंद्र है और इनमें 766 मतदान केंद्र ऐसे हैं, जो बड़े भवनों में हैं। इस बार भी निगम 70 से ज्यादा आदर्श मतदान केंद्र बनाने की तैयारी में है और वहां थ्रीआर कान्सेप्ट पर मतदान केंद्रों को सजाया जाएगा और साथ ही स्वच्छता का संदेश देते मतदान केंद्र भी बनाए जाएंगे। नगर निगम की टीमों द्वारा मतदान केंद्रों और उसके आसपास होने वाले कार्यों को लेकर सूची बना ली गई थी। रिपोर्ट मिलने के बाद क्षेत्रीय अपर आयुक्त ने अफसरों के साथ दौरा कर वहां कराए जाने वाले कार्यों को लेकर अपनी सहमति दी है और अब इसके बाद निगम ने निर्वाचन कार्यालय से कार्यों को लेकर टेंडर जारी करने की अनुमति ली थी।अब उस मान से टेंडर जारी कर कार्य शुरू कराए जा रहे हैं। अपर आयुक्त अभय राजनगांवकर के मुताबिक शहरी क्षेत्र में 1760 मतदान केंद्र है और इनमें से 70 मतदान केंद्रों को आदर्श मतदान केंद्र बनाया जाना है, इनमें महिला मतदान केंद्र, विकलांग मतदान केंद्र के साथ साथ कई अन्य आदर्श मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, जहां मतदान केंद्रों को बेहतर ढंग से सजाया जाएगा। पिछली बार भी यह प्रयोग खासा चर्चा में रहा था और इस बार भी निगम थ्रीआर कान्सेप्ट के साथ साथ स्वच्छता को लेकर यह कार्य करने जा रहा है। कई मतदान केंद्रों पर वेस्ट से बेस्ट की कलाकृतियां लगाकर सजाया जाएगा तो कहीं तमाम सुविधाएं जुटाकर आदर्श मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इसके लिए कुछ बड़ी एजेंसियों को काम सौंपा जा रहा है और वहां किस थीम पर कार्य होगा, यह पहले से प्लानिंग कर उसी मान से कार्य कराए जाएंगे। इसके अलावा सामान्य मतदान केंद्रों पर बिजली, पानी, सुविधाघर से लेकर रंग रोगन से लेकर तमाम कार्यों की शुरुआत अलग अलग झोनों के मतदान केंद्र पर शुरू कर दी गई है और कुछ जगह शुरू होना है।

मंदिर के नाम की जमीन भी नहीं छोड़ता भूमाफिया

इंदौर। भूमाफिया की माया ही गजब है। ये आदमी तो ठीक भगवान को भी नहीं बख्शते, ऐसा इंदौर जिला प्रशासन के सर्वे से सामने आया है। पता चला कि जिले में 40 ऐसे मंदिर हैं जिनके आधिपत्य की जमीन पर कहीं मकान, कहीं दुकान बन गई। कहीं-कहीं तो कालोनी भी कट गई। यह तो जांच हो गई तो पता चल गया नहीं तो और भी घपला संभव था। दरअसल, इसमें लापरवाही के साथ आस्था की भी भागीदारी है। हमारी संस्कृति और संस्कार में भगवान इस तरह निष्ठुर हो ही नहीं सकते, इसलिए इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि मंदिर यानी भगवान की संपत्ति की ओर कोई नजर उठा सकता है। अब कलयुग है और भूमाफिया सक्रिय हैं तो यह संभव है। भगवान की जमीन पर किसी भी तरह का कब्जा स्वीकार नहीं किया जा सकता। स्वयं ईश्वर भी इसे गलत ही मानेंगे इसलिए ऐसे लोगों को सजा में किसी भी तरह की रियायत नहीं मिलनी चाहिए।

चिकित्सा व्यवस्था में ठेका- इसमें कोई दूसरी राय हो ही नहीं सकती कि स्वास्थ्य और चिकित्सा व्यवस्था बेहद संवेदनशील विषय है। इसमें न लापरवाही होनी चाहिए, न समझौता। प्रदेश में मेडिकल कालेज से संबद्ध बड़े अस्पतालों में अनुबंध के आधार पर जांच आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। संभवतः सरकारी स्तर पर इनका प्रबंधन व इनमें लगने वाला निवेश मुश्किल होता है इसलिए यह व्यवस्था अपनाई जाती है लेकिन निगरानी का तंत्र कमजोर होने पर मुश्किल आती ही है। एमवाय अस्पताल में 31 मार्च को निजी डायग्नोस्टिक सेंटर से अनुबंध खत्म हुआ। समय सीमा भी बढ़ाई गई लेकिन इससे उपजे संशय से मरीजों को काफी परेशानी हुई। दो-तीन दिन से जांच आदि का काम प्रभावित रहा। सरकारी अस्पतालों में ऐसा इसलिए भी नहीं होना चाहिए क्योंकि यहां आर्थिक रूप से कमजोर मरीज भी आते हैं। वैसे निजी कंपनियों द्वारा बेहतर ढंग से सरकारी अस्पताल भी संचालित किए जा रहे हैं। पड़ोसी राज्य गुजरात में इसके उदाहरण हैं।

आस्था के नाम पर ठगी के दुष्परिणाम- इंदौर के नजदीक उज्जैन में भगवान महाकाल की ख्याति की कोई सीमा नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल होने के कारण भी देश-विदेश से श्रद्धालु यहां आते हैं। श्री महाकाल महालोक निर्माण के बाद तो इसकी ख्याति द्विगुणित हो गई है। अब भीड़ है तो दर्शन के लिए व्यग्रता भी होगी ही। इसी का फायदा कतिपय स्वार्थी तत्व उठाते हैं और विशेषकर बाहरी राज्यों से आए श्रद्धालुओं में से कुछ ठगी का शिकार हो जाते हैं। कभी-कभी मामले पुलिस तक पहुंच जाते हैं और शहर की छवि मलिन होती है। क्षुद्र स्वार्थ का नुकसान इन लोगों को समझ नहीं आता लेकिन इन्हें श्रद्धालुओं की भावना का श्राप जरूर मिलता है। सर्वशक्तिमान की नगरी में रहने वाले ये लोग यह भी भूल जाते हैं कि ऊपरवाला उन्हें देख रहा है और उसका कोपभाजन नहीं बनना चाहिए।

लक्ष्य पूरा करना ही चुनौती

गर्मी आते ही जल संरक्षण के उपाय की बात करना हर साल की परंपरा है। इस बार आईटी सिटी बेंगलुरू में जलसंकट सुर्खियां बना और इंदौर का नाम भी संभावित जलसंकट वाले 10 शहरों में आ गया तो शहरवासियों की धड़कनें स्वाभाविक रूप से बढ़ गईं। शहर में जहां नर्मदा जल की सप्लाई नहीं है, वहां के रहवासी जलसंकट से हर वर्ष जूझते हैं क्योंकि एकमात्र सहारा बोरवेल साथ छोड़ देते हैं। जैसे-तैसे दो महीने गुजरते हैं, मानसून आता है और जल संरक्षण की चर्चा नेपथ्य में चली जाती है। वंदे जलम महाअभियान की शुरुआत करते हुए नगर निगम के आयोजन में 50 हजार स्थानों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का लक्ष्य तय किया गया। भवनों के नक्शे में भी इनका प्रविधान होता है लेकिन बच निकलने की गलियां भी हैं इसलिए लक्ष्य पूरा होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। उपाय सख्ती ही है और नगर निगम प्रशासन को ही करनी होगी।

राजस्व देने के मामले में 65 करोड़ पीछे रह गया इंदौर

इंदौर। प्रदेश में राजस्व देने के मामले में इंदौर परिवहन कार्यालय हमेशा अव्वल रहा है। तय लक्ष्य से हमेशा अधिक राजस्व एकत्र किया गया, लेकिन वित्त वर्ष 2023-24 में इंदौर लक्ष्य से 65 करोड़ रुपये पीछे रह गया। मार्च में उज्जैन में आयोजित हुए व्यापार मेले की वजह से इंदौर पिछड़ गया। 15 लाख से अधिक कीमत के वाहन उज्जैन व्यापार मेले में पंजीकृत होने से इंदौर का राजस्व प्रभावित हुआ। अनुमान के अनुसार इंदौर में पंजीकृत होने वाले करीब 500 वाहन उज्जैन में पंजीकृत हुए।ग्वालियर की तर्ज पर पहली बार उज्जैन में व्यापार मेला आयोजित किया गया। यहां मिलने वाली छूट की वजह से आसपास के परिवहन कार्यालयों में पंजीकृत होने वाले वाहन उज्जैन में पंजीकृत हुए। इससे सर्वाधिक प्रभावित इंदौर परिवहन कार्यालय हुआ।इंदौर में पंजीकृत होने वाले मालवा-निमाड़ के अधिकांश वाहन व्यापार मेले की वजह से उज्जैन में पंजीकृत हुए। इस कारण इंदौर परिवहन कार्यालय 931.26 करोड़ का राजस्व लक्ष्य हासिल नहीं कर सका। वित्त वर्ष 2023-24 में परिवहन विभाग ने 865.42 करोड़ रुपये राजस्व एकत्र किया।

मार्च माह में 44 करोड़ राजस्व

इंदौर परिवहन कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष के आखिरी माह में तमाम प्रयास के बाद भी 44.73 करोड़ रुपये ही राजस्व एकत्र हो पाया। यह पूरे वित्त वर्ष के सभी माह के सबसे कम आंकड़ा रहा। 2022-23 मार्च के 78.49 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त हुआ था, लेकिन वित्त वर्ष 2023-24 के मार्च में 36 करोड़ रुपये पीछे रह गया।

वर्ष 2022-23 से भी 26 करोड़ पीछे

इंदौर परिवहन कार्यालय ने वित्त वर्ष 2022-23 में प्रदेश में सर्वाधिक 891.84 करोड़ रुपये राजस्व एकत्र कर रिकार्ड बनाया था। इसको देखते हुए शासन स्तर से वित्त वर्ष 2023-24 में इंदौर परिवहन कार्यालय को 931.26 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य दिया गया। इसमें विभाग 865.42 करोड़ रुपये ही जमा कर पाया, जो वित्त वर्ष 2022-23 की अपेक्षा 26 करोड़ रुपये कम है।

आचार संहिता लगने के बाद भी नही हटे शहर से होर्डिंग,पोस्टर

आचार संहिता लगने के 72 घंटे बाद निगम,पुलिस,और परिवहन विभाग को है होर्डिंग हटाने के निर्देश

इंदौर। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के 72 घंटे के अंदर संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत नगर निगम पुलिस एवं परिवहन विभाग को तुरंत कार्रवाई कर नेताओं के होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, चुनाव चिन्ह एवं शासकीय योजनाओं के पोस्टर हटाने के निर्देश है। जिले में आचार संहिता लागू होने के बावजूद अभी तक इस नियम को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई जगह-जगह सरकारी योजनाओं के पोस्टर एवं नेताओं के फोटो व चुनाव चिन्ह दीवारों पर लगे दिखाई दे रहें हैं जो नगर निगम एवं पुलिस व परिवहन विभाग को नजर नहीं आए हैं। अधिकांश दीवारों पर विधायक मंत्री के साथ ही देश व प्रदेश के आला नेताओं के नाम चुनाव चिन्ह आदि बने हुए हैं उन्हें हटाने को लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस लगातार कार्रवाई का दावा कर रही हैं वाहनों की जांच एवं चालानी कार्रवाई के लिए शाम होते ही भारी बल तैनात किया जा रहा है किंतु अभी तक उनकी नजर ऑटो रिक्शा या निजी वाहनों पर लगे दल विशेष के चुनाव चिन्ह के साथ ही शासकीय योजनाओं के पोस्टर जिस पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के फोटो

मंदिर और सरकारी जमीन के बाद नजूल की जमीन भी मुक्त करवाएगा जिला प्रशासन

इंदौर। सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण और मंदिरों की जमीन को खाली कराने के साथ ही अब जिला प्रशासन नजूल की लीज भूमि पर भी कार्रवाई की शुरुआत करने जा रहा है। जिले की 108 भूमि जो लीज पर दी गई है उनसे राजस्व वसूली का अभियान शुरू किया जा रहा है। इन 108 लीज भूमि में से 73 का नवीनीकरण होना शेष है। उक्त प्रकरणों के आधार पर जल्द ही नवीनीकरण की कार्रवाई भी शुरू की जा रही है। अपर कलेक्टर सपना लोवंशी ने बताया कि जिले की सभी नजूल की लीज पर दी गई भूमियों को लेकर अभियान शुरू किया जा रहा है समस्त प्रकरण निकालकर उनकी लीज अवधि का परीक्षण करने के साथी नवीनीकरण के मामलों को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। जिन लीजधारकों ने अभी तक भू भाटक जमा नहीं किया है उनसे वसूली भी जल्द से जल्द की जाएगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012 से जिले में नजूल भूमि को लेकर विशेष अभियान चलाया गया और प्रत्येक भूमि के लीज प्रकरण को खंगाल कर लीज धारक से दस्तावेज तथा किए गए अनुबंध का परीक्षण करने के बाद राशि जमा कराई गई थी। उसके बाद से जिले में सतत कार्रवाई हुई और कुछ जमीनों की लीज निरस्त करने का काम भी हुआ है। वर्तमान में प्रशासन के पास 108 लीज पर दी गई भूमियों की जानकारी है जिन पर बकाया भू भाटक की वसूली अब की जाएगी।

3 सेक्टर में शुरू हुआ रेसीडेंसी क्षेत्र का सर्वेक्षण

अपर जिला दंडाधिकारी सपना लोवंशी ने बताया कि रेसीडेंसी क्षेत्र की भूमि को लेकर शुरू किए गए दस्तावेजीकरण के कार्य में अधिकांश लोगों ने अपने दस्तावेज अभी तक जमा नहीं किए हैं। दो बार अधिसूचना जारी करने के बावजूद लोगों की रुचि इसमें नजर नहीं आई है स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया अब इस क्षेत्र को तीन अलग-अलग सेक्टर में बांटकर एसडीएम को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे अपने सेक्टर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र तथा कॉलोनी के रहवासियों से उनके पास उपलब्ध दस्तावेज एकत्रित कर प्रस्तुत करेंगे जिसके आधार पर इस क्षेत्र का सर्वेक्षण पूर्ण होगा एवं उसका राजस्व रिकार्ड तैयार किया जाएगा।

दिव्यांग मतदाताओं के लिए नहीं छपे मतपत्र

इंदौर। लोकसभा चुनाव में 85 वर्ष से अधिक आयु तथा दिव्यांग मतदाताओं को विधानसभा चुनाव की तरह घर पर मतदान की सुविधा का लाभ देने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने के लिए छूट दी गई है, लेकिन उक्त प्रारूप अभी तक आयोग द्वारा प्रकाशित करवाकर सभी जिला निर्वाचन कार्यालय को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ही नहीं कराए गए हैं। अधिकांश जिलों से दल उक्त प्रारूप के लिए दो बार भोपाल जाकर खाली हाथ लौट आए हैं। अब अधिकारी असमंजस में हैं कि लोगों की मांग कैसे पूरी की जाए। 7 चरणों में मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराने के आयोग की घोषणाओं के बाद सभी जिले अपने-अपने क्षेत्र की चुनाव व्यवस्था में लग गए हैं। लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन 12 डी आवेदन अब तक नहीं छप पाए हैं। इसके चलते इस बार घर बैठे मतदान करने की सुविधा में भी लेटलतीफी हो सकती है।अब तक 12 डी फॉर्म ही नहीं आए हैं, जिसके कारण कई जिलों के दल बार-बार भोपाल के चक्कर लगाकर खाली हाथ लौट आए हैं। ज्ञात हो कि आयोग ने घर बैठे मतदान करने की सुविधा लेने वाले वर्ग की उम्र बढ़ा दी है। अब 80 साल की जगह 85 साल तक के बुजुर्गों को ही इस सुविधा का लाभ मिलेगा। शुरू के 4 चरणों में मध्यप्रदेश में होगा मतदान लोकसभा चुनाव के लिए घोषित किए गए सात चरणों में से शुरू के चार चरणों में ही मध्यप्रदेश में चुनाव होंगे।19 अप्रैल, 26 अप्रैल को पहले और दूसरे चरण में मतदान कराया जाएगा, वहीं 7 व 13 को तीसरे और चौथे चरण का मतदान होगा, जिसमें मध्यप्रदेश के सभी जिलों में चुनाव संपन्न होंगे, लेकिन अब तक 12 डी की प्रक्रिया शुरू नहीं होने के कारण मतदाता असमंजस में है और अपने-अपने जिले के चुनाव अधिकारियों से जाकर फॉर्म की मांग भी कर रहे हैं। अन्य जिलों में नौकरी करने वाले परेशान उक्त सुविधा से इस बार आयोग ने पत्रकारों को भी जोडऩे की तैयारी करते हुए उन्हें डाक मतपत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। पत्रकारों को डाक मतपत्र के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना है, किंतु अभी तक प्रारूप ही नहीं मिल पाया है। कई लोग इंदौर में काम करने वाले अन्य जिलों के मतदाता हैं। पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा, लेकिन अभी तक 12 डी फॉर्म ही नहीं भर पाए हैं।

नियमों की जानकारी ही नहीं

इंदौर जिले के जिम्मेदारों को पत्रकारों को दी जाने वाली इस सुविधा के नियमों की सही जानकारी नहीं है। उनके अनुसार अधिमान्य पत्रकारों को ही इस सुविधा का लाभ मिलेगा। सभी पत्रकारों को डाकमत पत्र जारी नहीं होंगे, जबकि आयोग ने अपने निर्देश में स्पष्ट कहा है कि आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान कवरेज के लिए आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले प्राधिकार पत्रधारक पत्रकारों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। प्राधिकार पत्र को निर्वाचन कार्यालय और जनसंपर्क कार्यालय अधिमान्यता से जोड़कर नए नियम दर्शाता नजर आ रहा है। पत्रकारों को इस सुविधा के लाभ के लिए जिला कार्यालय से जनसंपर्क के माध्यम से जारी होने वाले प्राधिकार पत्र की आवश्यकता होगी, किंतु अभी तक किसी भी चरण में होने वाले मतदान के लिए आयोग एवं जिला कार्यालय द्वारा प्राधिकार पत्र तैयार ही नहीं किए गए हैं, जबकि आचार संहिता से पूर्व ही जनसंपर्क के माध्यम से संस्थान से पत्रकारों के नाम एवं फोटो लेकर जानकारी एकत्रित कर ली गई थी।

उम्मीदवार के खाते में जुड़ेगा प्रचार के लिए एसएमएस भेजने का खर्च जुड़ेगा

इंदौर। लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान उम्मीदवार द्वारा थोक में भेजे जाने वाले एसएमएस का खर्च भी संबंधित उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जाएगा। प्रचार अवधि के दौरान वैकल्पिक निर्वाचन के प्रचार के लिए बल्क (थोक) में भेजे गए एसएमएस की जानकारी रिटर्निंग अधिकारी को मिलने पर वह सेवा प्रदाता से इस पर हुए व्यय का अनुमान लगवाकर इसे अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के खाते में जोड़ देगा। निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग के अनुसार मतदान संपन्न होने के लिए निश्चित किए गए समय की समाप्ति से 48 घंटे पहले तक की अवधि के दौरान राजनैतिक प्रकृति के थोक में एसएमएस भेजने पर प्रतिबंध होगा। राज्य में मोबाइल सेवा प्रदाता सभी संबंधितों के नोटिस में ऐसे थोक एसएमएस की जानकारी तुरंत लायें, ऐसे निर्देश दिए गए है। आयोग के ध्यान में यह भी आया है कि चुनाव में निहित स्वार्थी व्यक्तियों द्वारा निर्वाचन विधि के प्रावधानों, आदर्श आचरण संहिता और इस संबंध में जारी निर्देशों का उल्लंघन करते हुए कुछ आपत्तिजनक संदेश भी एसएमएस द्वारा भेजे जाते हैं। चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण प्रक्रिया के साथ संपन्न करवाने के लिए भी आयोग ने निर्देश जारी किए हैं। ऐसे आपत्तिजनक एसएमएस के लिए पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए गए है कि वह विशेष मोबाइल नंबरों को प्रचारित करें जिन पर एसएमएस प्राप्तकर्ता उक्त एसएमएस को अग्रेषित कर सके। पुलिस पहले उचित जांच करें और एसएमएस भेजने वाले का पता लगाये तथा भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 तथा आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देशों और इस मामले में लागू अन्य कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाये।

31 अगस्त तक लेंगे 30 फीसदी कम्पाउंडिंग के आवेदन

इंदौर। पिछले दिनों शासन ने 30 फीसदी तक अवैध निर्माणों को वैध करने के लिए कम्पाउंडिंग की ठप पड़ी प्रक्रिया को फिर से शुरू करवाया। पूर्व में इस बारे में जो आदेश दिए थे उसमें कुछ विसंगतियां थीं। हालांकि नगर निगम ने लगभग 100 करोड़ रुपए की राशि हासिल कर ली थी। अब 31 दिसम्बर 2021 के पूर्व बनी बिल्डिंगों में ही कम्पाउंडिंग की अनुमति रहेगी। उसके लिए भी नक्शा मंजूर होना अनिवार्य है। साथ ही एमओएस पार्किंग में किए गए निर्माण वैध नहीं होंगे और उपयोग परिवर्तन भी मंजूर नहीं किया जाएगा। अभी निगम के भवन अधिकारियों ने लगभग 30 बिल्डिंगें ढूंढी है तो कम्पाउंडिंग के दायरे में आ सकती है। विधानसभा चुनाव से पहले शासन ने 10 की बजाय 30 फीसदी तक कम्पाउंडिंग करने की सुविधा दी थी। मगर उन्हीं निर्माणों को इसके दायरे में लिया जा सकता है जिनके मंजूर करवाए गए।उदाहरण के लिए आवासीय या वाणिज्यिक नक्शा मंजूर करवाने के बाद बिल्डर ने 30 फीसदी या उससे अधिक अवैध निर्माण कर लिया है तो उसमें से स्वीकृत योग्य 30 फीसदी को वैध किया जा सकेगा। मगर पार्किंग और एमओएस में किए गए निर्माण इस श्रेणी में नहीं आएंगे। उस वक्त बिल्डरों को यह सुविधा दी गई कि वे अपने अवैध निर्माणों का सेल्फ असेसमेंट करते हुए ऑनलाइन आवेदन के साथ कम्पाउंडिंग की राशि जमा कर दें। तब ताबड़तोड़ शहर के बिल्डरों ने यह राशि जमा कर दी, जो कि लगभग 100 करोड़ रुपए होती है। मगर इसमें कुछ विसंगतियां और शिकायतें प्राप्त हुई। दरअसल कुछ होशियार बिल्डरों ने अपने चल रहे प्रोजेक्टों में भी 30 फीसदी अधिक अवैध निर्माण कर यह राशि जमा कर दी। जबकि शासन की मंशा पूर्व में हो चुके निर्माणों को लेकर थी। लिहाजा अब जो शासन ने नए सिरे से आदेश जारी किए उसमें कम्पाउंडिंग के लिए कट ऑफ डेट अवैध कॉलोनियों की तरह तय कर दी। अब 31 दिसम्बर 2021 तक या उससे पूर्व निर्मित बिल्डिंगों या स्वयं के आवास में ही 30 फीसदी तक कम्पाउंडिंग का लाभ मिलेगा और इसके लिए भी 31 अगस्त तक आवेदन करना होंगे। सभी झोनों से निगम ने इस तरह की बिल्डिंगों को चिन्हित करना शुरू किया और लगभग 30 बिल्डिंगें ढूंढी हैं, जिनकी कम्पाउंडिंग हो सकती है।

85 साल से अधिक के मतदाता को घर पर मतदान की है छूट

इंदौर। लोकसभा चुनाव में 85 वर्ष से अधिक आयु तथा दिव्यांग मतदाताओं को विधानसभा चुनाव की तरह घर पर मतदान की सुविधा का लाभ देने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने के लिए छूट दी है। उक्त प्रारूप अभी तक आयोग द्वारा प्रकाशित करवा कर सभी जिला निर्वाचन कार्यालय को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ही नहीं कराए गए हैं। अधिकांश जिलों से दल उक्त प्रारूप के लिए दो बार दल भोपाल जाकर खाली हाथ लौट आया है। उक्त सुविधा से इस बार आयोग ने पत्रकारों को भी जोड़ने की तैयारी करते हुए उन्हें डाक मत पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। पत्रकारों को डाक मत पत्र के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना है किंतु अभी तक प्रारूप ही नहीं है वही जिले के जिम्मेदारों को पत्रकारों को दी जाने वाली इस सुविधा के नियमों की सही जानकारी नहीं है वह कह रहे हैं कि अधिमान्य पत्रकारों को ही इस सुविधा का लाभ मिलेगा सभी पत्रकारों को डाकमत पत्र जारी नहीं होंगे। आयोग ने अपने निर्देश में स्पष्ट कहा है कि आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान कवरेज के लिए आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले प्राधिकार पत्र धारक पत्रकारों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। प्राधिकार पत्र को निर्वाचन कार्यालय और जनसंपर्क कार्यालय अधिमान्यता से जोड़कर नए नियम दर्शाता नजर आ रहा है। पत्रकारों को इस सुविधा के लाभ के लिए जिला कार्यालय से जनसंपर्क के माध्यम से जारी होने वाले प्राधिकार पत्र की आवश्यकता होगी किंतु अभी तक किसी भी चरण में होने वाले मतदान के लिए आयोग एवं जिला कार्यालय द्वारा प्राधिकार पत्र तैयार ही नहीं किए गए हैं जबकि आचार संहिता से पूर्व ही जनसंपर्क के माध्यम से संस्थान से पत्रकारों के नाम एवं फोटो लेकर जानकारी एकत्रित कर ली गई थी।

दैनिक सद्भावना पाती
इंदौर, शुक्रवार 05 अप्रैल, 2024

संपादकीय | केंद्रीय एजेंसियों का दायरा और सीजेआई की नसीहत

पिछले कुछ वर्षों से केंद्रीय जांच एजंसियों की कार्यप्रणाली लगातार प्रश्नांकित होती रही है। कई मौकों पर अदालतें भी उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही याद दिला चुकी हैं। उसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने भी कहा कि जांच एजंसियों को उन अपराधों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो देश की सुरक्षा, आर्थिक स्थिति और लोकव्यवस्था के लिए असल में खतरा पैदा करते हों। उन्होंने इस पक्ष को भी रेखांकित किया कि जांच अनिवार्यताओं और व्यक्तिगत गोपनीयता अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की तत्काल आवश्यकता है। प्रधान न्यायाधीश के इस कथन को प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और आयकर विभाग की पिछले कुछ सालों में की गई छापेमारी और गिरफ्तारियों, जब्ती वगैरह के मद्देनजर देखें, तो स्थितियां स्वत- स्पष्ट हो जाती हैं। हालांकि प्रधान न्यायाधीश की इस नसीहत को जांच एजंसियां कितनी गंभीरता से लेंगी और उस पर कितना अमल करेंगी, कहना मुश्किल है। बेशक प्रधान न्यायाधीश ने ये बातें सीबीआइ के ही एक आयोजन में कहीं। मगर जैसा कि अनेक मामलों में देखा जाता है, सार्वजनिक मंचों से कही बातों को अक्सर आदर्श वक्तव्य की तरह केवल सुन लिया जाता है, उन पर अमल करना जरूरी नहीं समझा जाता। सीबीआइ भी ऐसा ही करे, तो हैरानी की बात नहीं। केंद्रीय जांच एजेंसियोंपर लंबे समय से आरोप लगते रहे हैं कि वे सरकार के इशारे और उसकी इच्छा के अनुरूप काम करती हैं। पिछले कुछ वर्षों में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के इरादे से लगातार की जा रही कार्रवाइयों के मद्देनजर ये आरोप निरंतर गाढ़े होते गए हैं। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि अधिकतर कार्रवाइयां

विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ ही की गई हैं। उसमें कई नेताओं को सलाखों के पीछे भी डाला गया। अनेक मामलों में आरोप लगते रहे कि गलत तरीके से जब्ती की गई, पूछताछ के नाम पर लोगों को नाहक परेशान और प्रताड़ित किया गया।

यह सवाल भी लगातार पूछा जाता है कि जांच एजंसियां जितने छापे मारती और कार्रवाइयां करती हैं, उनमें से पांच फीसद मामलों में भी दोष सिद्ध नहीं हो पाते। धनशोधन निवारण कानून की धाराएं इतनी सख्त हैं कि उनके तहत गिरफ्तार किए गए लोगों को तब तक जमानत नहीं दी जाती, जब तक कि वे निर्दोष साबित नहीं हो जाते। इसलिए सर्वोच्च अदालत ने पहले भी कहा था कि इस कानून के तहत गिरफ्तारी से पहले जांच एजंसियों को पूरी तरह आश्वस्त होना चाहिए कि मामले में दोषसिद्धि की कितनी संभावना है। मगर इसे भी गंभीरता से नहीं लिया गया।

ताबड़तोड़ छापों से परेशान होकर विपक्षी दलों ने इन पर रोक लगाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगाई, तब अदालत ने कहा था कि धनशोधन का मामला आतंकवादी और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से भी जुड़ा हो सकता है, इसलिए एजंसियों को इस काम से रोका नहीं जा सकता। अब प्रधान न्यायाधीश ने जांच एजंसियों का दायरा स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें उन्हीं मामलों पर अपना ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, जिनसे राष्ट्र की सुरक्षा, आर्थिक स्थिति और लोकव्यवस्था को खतरा पैदा होता हो। उसमें व्यक्ति के निजी अधिकारों की सुरक्षा का भी ध्यान रखने की जरूरत है। जांच एजंसियां जांच के नाम पर अक्सर व्यक्तियों के फोन, कंप्यूटर जैसे निजी उपकरण भी जब्त कर लेती हैं, जिनमें उनकी व्यक्तिगत सामग्री हो सकती है। इन नैतिक और कानूनी तकाजों का ध्यान एजंसियां तभी रख सकती हैं, जब उनमें वास्तव में स्वतंत्र रूप से काम करने की इच्छाशक्ति हो।

सोशल मीडिया से...

भाई सुशील मोदी की स्वास्थ्य संबंधित खबर सुन हैरान और दुखी हूँ। 50 वर्षों से उन्हें जानता हूँ वो जुझारू और संघर्षशील प्रवृति के धनी है। परमपिता से उनके अच्छे स्वास्थ्य की मंगलकामना करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो शीघ्र स्वस्थ होकर सार्वजनिक जीवन एवं जनसेवा में सक्रिय हों ताकि उनके लंबे राजनीतिक अनुभव का सबको फायदा मिलते रहे।

लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री

मैं कहना चाहता हूँ जो लोग डर, लालच और अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। जब तक मैं इस पार्टी को कार्यकर्ता के रूप में लीड करूँगा कभी भी इस पार्टी के दरवाजे उनके लिए नहीं खोलूंगा।

जीतू पटवारी
मध्य प्रदेश के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री

राज्य उपभोक्ता आयोग की सख्त कार्रवाई - जिला उपभोक्ता आयोग की सदस्य को हटाया

इंदौर। रजिस्ट्रार मप्र राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग-भोपाल ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग इंदौर-1 की सदस्य साधना शर्मा के विरूद्ध उनके आचारण एवं कार्य व्यवहार को लेकर लगातार मिलने वाली शिकायतो के बाद उन्हें हटा दिया है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग इंदौर-1 के अध्यक्ष ने राज्य आयोग को पत्र के माध्यम से सूचना दी थी कि सदस्य शर्मा के जिला आयोग इंदौर 1 के सदस्य रहते हुए न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य किया जाना संभव नहीं है। उन्हें जिला उपभोक्ता आयोग इंदौर-1 में रखना न्यायिक एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। लोकसभा निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने से उनका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से सदस्य जिला उपभोक्ता आयोग इंदौर-1 साधना शर्मा, का संलग्नीकरण जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग उज्जैन में कर दिया है।

निर्वाचन में लगे अधिकारी-कर्मचारियों को दिया जायेगा प्रशिक्षण, तैयारियां पूर्ण

इंदौर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह के निर्देशन में इंदौर जिले में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न कराने हेतु सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में निर्वाचन में लगे अधिकारी-कर्मचारियों को व्यवस्थित रूप से निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराने हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी डिप्टी कलेक्टर सुदीप मीणा ने बताया कि निर्वाचन में संलग्न अधिकारी-कर्मचारियों को चरणवार प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रथम चरण का प्रशिक्षण कार्यक्रम 15, 16, 18 और 19 अप्रैल 2024 को शासकीय होलकर कॉलेज में आयोजित किया जायेगा जिसमें लगभग 9 हजार अधिकारी-कर्मचारी प्रशिक्षण लेंगे। प्रशिक्षण में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गये दिशा-निर्देश, प्रक्रिया, नियम और अधिनियमों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी जायेगी।

कच्चाथिवू क्या सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा?

अजय सेतिया

लोकसभा और विधानसभा के हर चुनाव में कच्चाथिवू मुद्दा बनता रहा है। जयललिता ने 2011 के विधानसभा चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाकर करुणानिधि सरकार को हरा दिया था। मुख्यमंत्री बनते ही जयललिता ने 1974 और 1976 के समझौतों को असंवैधानिक ठहराते हुए उन्हें रद्द करवाने के लिए सुप्रीमकोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की थी। सुप्रीमकोर्ट ने बेरुबारी केस में फैसला दिया हुआ था कि किसी भी देश के साथ हुए समझौते की संविधान संशोधन के अंतर्गत संसद से पुष्टि करवाई जानी चाहिए।अगस्त 2013 में मनमोहन सिंह सरकार ने सुप्रीमकोर्ट में एक हल्फिया बयान दिया जिसमें सरकार की तरफ से कहा गया था कि कच्चाथिवू ब्रिटिश भारत और श्रीलंका में विवादास्पद था क्योंकि समुद्री सीमाओं का सीमांकन नहीं हुआ था। नमोहन सरकार ने हल्फिया बयान में यह भी कहा कि भारत का कोई क्षेत्र किसी को नहीं दिया गया है। क्योंकि दोनों देशों की समुद्री सीमाओं का सीमांकन नहीं हुआ था इसलिए क्षेत्र विवादास्पद था।

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आरोप को पूरी तरह नकार दिया है कि इंदिरा गांधी ने भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित कच्चाथिवू द्वीप 1974 में श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए इस मुद्दे को उठाया था, उसके बाद वह हर चुनावी रैली में इस मुद्दे को उठा रहे हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने भी भाजपा के मंच से प्रेस कांफ्रेंस करके प्रधानमंत्री मोदी के आरोप की पुष्टि की है। कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी से प्रेस कांफ्रेंस करवा कर दो मकसद साधे हैं। एक तो उन अटकलों पर रोक लगा दी है कि वह भाजपा ज्वाईन करके आनंदपुर साहिब के बजाए चंडीगढ़ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, दूसरे उन्होंने मोदी के आरोप का किसी भी अन्य कांग्रेस नेता के मुकाबले बेहतर ढंग से खंडन किया।

उन्होंने कहा कि जिस प्रधानमंत्री ने दक्षिण एशिया का नक्शा बदल कर बांग्लादेश नाम का अलग राष्ट्र बना दिया, क्या वह भारत की जमीन का एक भी ईंच किसी अन्य देश को दे सकती थी। अलबत्ता उन्होंने मोदी सरकार के समय चीन की तरफ से भारत के भूभाग पर कब्जा करने और बांग्लादेश को जमीन के आदान प्रदान में दस गुना जमीन बांग्लादेश को देने जैसे कुछ टेढ़े सवाल भी उठाए।

आरोप और खंडन के बीच कच्चाथिवू का इतिहास कुछ और कहता है। रामेश्वरम शिलालेख के अनुसार 1187 से 1196 तक श्रीलंका के राजा निस्संका मल्ला थे, उन्होंने श्रीलंका अधिकार क्षेत्र वाले टापूओं का भ्रमण किया था। श्रीलंका के इर्दगिर्द कच्चाथिवू जैसे कुल 11 टापू हैं, इनमें कच्चाथिवू भारत की तरफ आखिर में है।

एतिहासिक तथ्य यह है कि मध्यकाल तक कच्चाथिवू श्रीलंका के अधीन ही था। लेकिन सत्रहवीं सदी में भारत के मदुरै जिले की रामनाथपुरम सब डिविजन की राजशाही के अधीन हो गया था। 1870 में रामनाथपुरम के राजा (जमीन) ने डच कंपनी को कच्चाथिवू टापू पांच साल की लीज पर दिया था, जिसे 1890 तक बढाया जाता रहा। ब्रिटिश राज के समय कच्चाथिवू मद्रास प्रेसीडेंसी के अंतर्गत था। 1920 में जब ब्रिटिश नौसेना ने इस निर्जन टापू का प्रेक्टिस के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया, तब टापू पर नियन्त्रण का विवाद शुरू हुआ। भारत की ब्रिटिश सरकार का मत था कि क्योंकि इस टापू पर रामनाथपुरम के राजा का अधिकार था इसलिए इस पर भारत की ब्रिटिश सरकार का अधिकार है।

एक समृद्ध भारतीय ईसाई मछुआरे श्रीनिवास पडईयाछी ने बीसवीं सदी की शुरुआत में ही कच्चाथिवू द्वीप में एक चर्च बनवा दिया था। लेकिन श्रीलंका ने कहा कि कच्चाथिवू पर बना सेंट एंटनी चर्च श्रीलंका की राजधानी जाफना के चर्च के अंतर्गत आता है, इसलिए कच्चाथिवू पर उसका अधिकार है। 1921 में भारत की ब्रिटिश सरकार और श्रीलंका सरकार ने एक समझौते में कच्चाथिवू को श्रीलंका का हिस्सा मान लिया। गलती वहीं से शुरू हुई।

आज़ादी के बाद तमिलनाडु में कच्चाथिवू की मल्कियत पर सवाल उठाया गया, लेकिन प्रधानमंत्री

जवाहर लाल नेहरू ने उस मांग को नजरअंदाज कर दिया। जबकि भारतीय मछुआरों के लिए यह टापू बहुत ही महत्वपूर्ण था। रामेश्वरम के मछुआरे वहां तक मछलियाँ पकड़ने जाते थे, और मछलियाँ पकड़ने के जाल सुखाने के लिए इस टापू का इस्तेमाल करते थे। लेकिन कच्चाथिवू पर मल्कियत का दावा दोनों तरफ से होता रहा। 1974 में इंदिरा गांधी ने तमिलनाडु की तरफ से कड़े विरोध के बीच समुद्री सीमांकन के द्विपक्षीय समझौते में कच्चाथिवू पर श्रीलंका का अधिकार स्वीकार कर लिया। यह समझौता रामसेतु और पाक स्ट्रेट के मध्य की समुद्री सीमा का सीमांकन करने के लिए हुआ था।

इसमें यह भी सहमति थी कि दोनों देशों के ईसाई अपने त्योहारों के मौके पर बिना पासपोर्ट और वीजा वहां जा सकेंगे। श्रीलंका और रामेश्वरम के ईसाई ईस्टर आदि त्योहारों के मौके पर वहां जाते हैं। 1974 के समझौते में यह भी था कि कच्चाथिवू के इर्दगिर्द दोनों देशों के मछुआरे मछलियाँ पकड़ने जा सकेंगे और अपना जाल सुखाने के लिए टापू का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1976 में भारत और श्रीलंका में बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी की समुद्री सीमा के सीमांकन का एक और समझौता हुआ। इस नए समझौते के मुताबिक़ दोनों देशों के मछुआरे एक दूसरे के क्षेत्र में मछलियाँ पकड़ने नहीं जाएंगे। इसके बाद समुद्री सीमा के सीमांकन का श्रीलंका, भारत और मालदीव में त्रिपक्षीय समझौता भी हुआ था।

1976 का समझौता भारतीय मछुआरों के हितों के खिलाफ था, जिसे श्रीलंका की नौसेना ने श्रीलंका के आंतरिक विद्रोह के समय कच्चाथिवू पर भी लागू कर दिया। भारत की संसद में इन समझौतों को रखा जरूर गया था, लेकिन संसद से इन समझौतों की पुष्टि नहीं करवाई गई थी। उस समय के विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह ने जब संसद में समझौते की जानकारी दी थी, तो द्रमुक सांसद इरा सेंझियन और फारवर्ड ब्लाक के सांसद मुकैया थेवर ने समझौते को असंवैधानिक करार देते हुए समझौते का विरोध किया था। संसद से समझौते की पुष्टि नहीं करवाई गई थी इसलिए कच्चाथिवू की मल्कियत श्रीलंका के हवाले किए जाने की वैधता को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी गई थी। तमिलनाडु के सीमान्त रामेश्वरम के मछुआरों के लिए यह टापू बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस क्षेत्र में जाते ही श्रीलंका की नौसेना भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लेती है, इसलिए टापू को दुबारा हासिल करने के लिए तमिलनाडु में कई बार आन्दोलन हो चुके हैं।

लोकसभा और विधानसभा के हर चुनाव में कच्चाथिवू मुद्दा बनता रहा है। जयललिता ने 2011 के विधानसभा चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाकर करुणानिधि सरकार को हरा दिया था। मुख्यमंत्री बनते ही जयललिता ने 1974 और 1976 के समझौतों को असंवैधानिक ठहराते हुए उन्हें रद्द करवाने के लिए सुप्रीमकोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की थी। सुप्रीमकोर्ट ने बेरुबारी केस में फैसला दिया हुआ था कि किसी भी देश के साथ हुए समझौते की संविधान संशोधन के अंतर्गत संसद से पुष्टि करवाई जानी चाहिए।अगस्त 2013 में मनमोहन सिंह सरकार ने सुप्रीमकोर्ट में एक हल्फिया बयान दिया जिसमें सरकार की तरफ से कहा गया था कि कच्चाथिवू ब्रिटिश भारत और श्रीलंका में विवादास्पद था क्योंकि समुद्री सीमाओं का सीमांकन नहीं हुआ था। मनमोहन सरकार ने हल्फिया बयान में यह भी कहा कि भारत का कोई क्षेत्र किसी को नहीं दिया गया है। क्योंकि दोनों देशों की समुद्री सीमाओं का सीमांकन नहीं हुआ था इसलिए क्षेत्र विवादास्पद था। कोई क्षेत्र हस्तांतरित नहीं किया गया है, इसलिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है।

मौजूदा मुख्यमंत्री स्टालिन के पिता और द्रमुक के प्रमुख करुणानिधी ने केंद्र की मनमोहन सरकार के इस हल्फिया बयान की कड़े शब्दों में निंदा की थी। उन्होंने कहा था कि सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में मौजूद दस्तावेज इस बात की पुष्टि करते हैं कि आज़ादी के समय कच्चाथिवू द्वीप भारत का हिस्सा था।

करुणानिधी ने अटल बिहारी वाजपेयी के एक बयान का हवाला दिया था, जिसमें वाजपेयी ने कथित तौर पर कहा था कि सोहार्दपूर्ण संबंधों के लिए भारत ने श्रीलंका के साथ गोपनीय समझौता किया था। तमिलनाडु में तो हर चुनाव में यह मुद्दा बनता रहा है, लेकिन यह पहला मौक़ा है जब किसी राष्ट्रीय दल ने कच्चाथिवू को चुनावी मुद्दा बनाकर पिछली केंद्र सरकारों को कटघरे में खड़ा कर दिया है।

शांतिपूर्ण एवं प्रलोभन मुक्त निर्वाचन के लिये सीमाओं पर रखें कड़ी निगरानी

भारत निर्वाचन आयोग ने सभी प्रदेशों के सीएस, डीजीपी एवं केन्द्रीय एजेन्सियों के प्रमुखों की बैठक लेकर दिये निर्देश

इंदौर। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनावों के दौरान कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा और आंकलन करने, अवैध गतिविधियों, जब्ती की रोकथाम और अंतर-राज्य और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। संयुक्त समीक्षा का उद्देश्य स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और प्रलोभन मुक्त चुनाव के लिए सीमाओं की रक्षा करने वाली केंद्रीय एजेंसियों के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के बीच सहज समन्वय और सहयोग के लिए सभी संबंधित हितधारकों को एक ही मंच पर लाना था। आयोग ने प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषयों की विस्तार से समीक्षा की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ ही राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और सीमाओं की रक्षा करने वाली केंद्रीय एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी शामिल हुये।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आयोग की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया और सभी हितधारकों से चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिये कि प्रत्येक मतदाता बिना किसी डर या भय के अपने मतदान के अधिकार का उपयोग कर सके। कुमार ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और एजेंसियों से स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भय-मुक्त चुनाव के लिए अपने %संकल्प% को ठोस %कार्रवाई% में बदलने का आह्वान किया।

बैठक में पड़ोसी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता, सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में पर्याप्त रूप से प्रदान की गई सीएपीएफ की तैनाती, सीमावर्ती राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में सीएपीएफ कर्मियों की आवाजाही और परिवहन के लिए साजो-सामान संबंधी सहायता, सीमावर्ती क्षेत्रों में उन फ्लैशपॉइंटों की पहचान और निगरानी करना जिनका चुनाव प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ सकता है, पिछले अनुभवों के आधार पर सांप्रदायिक तनाव को दूर करने के लिए निवारक, उपाय और अवैध गतिविधियों के खिलाफ खुली सीमाओं को सुरक्षित करने की अनिवार्यता आदि विषयों पर चर्चा हुई। आयोग ने अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार नशीले पदार्थों, शराब, हथियारों और विस्फोटकों सहित प्रतिबंधित वस्तुओं की आवाजाही पर अंकुश लगाने के लिए कड़ी निगरानी के महत्व को रेखांकित किया। कुछ राज्यों में अवैध गांजा की खेती पर अंकुश लगाने, सीमाओं पर शराब और नकदी की आवाजाही के लिए निकास और प्रवेश बिंदुओं की पहचान करने के निर्देश दिये। बैठक में मप्र की मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन, पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना एवं अधिकारी उपस्थित थे।

कानून एवं व्यवस्था संबंधी निर्देश

1. कड़ी निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमाओं पर एकीकृत जांच चौकियां। 2. सीमावर्ती जिलों के बीच अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर खुफिया जानकारी साझा करना। 3. अंतिम 48 घंटों के दौरान फर्जी मतदान को रोकने के लिए अंतरराज्यीय सीमाओं को सील करना। 4. सीमावर्ती जिलों की नियमित अंतरराज्यीय समन्वय बैठकें। 5. राज्य पुलिस द्वारा अंतरराज्यीय सीमावर्ती जिलों पर गश्त तेज करें। 6. सीमावर्ती राज्यों के समन्वय से रणनीतिक स्थानों पर अतिरिक्त नाके स्थापित किए जाएंगे। 7. मतदान के दिन अंतरराज्यीय सीमा सील करें। 8. सीमावर्ती राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के उत्पाद शुल्क आयुक्त परमिट की वास्तविकता की जांच सुनिश्चित करें, विशेष रूप से सीमावर्ती जिलों में शराब की दुकानों की औचक जांच करें। 9. लाइसेंसी हथियारों को समय पर जमा करना और गैर जमानती वारंटों का निष्पादन करना। 10. भगोड़ों, हिस्ट्रीशीटरों, चुनाव संबंधी अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही। 11. खतरे की आशंका के आधार पर राजनीतिक पदाधिकारियों/उम्मीदवारों को पर्याप्त सुरक्षा कवर।

व्यय निगरानी

1. अंतरराज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर अवैध शराब, नकदी, नशीली दवाओं के प्रवाह को रोकना। 2. चेकपोस्टों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर निगरानी को मजबूत करना। 3. पुलिस, आबकारी, परिवहन, जीएसटी एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त चेकिंग अभियान। 4. हेलीपैड, हवाई अड्डों, बस स्टेशनों और रेलवे स्टेशनों पर कड़ी निगरानी। 5. शराब और नशीली दवाओं के सरगनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई, देशी शराब के प्रवाह में कटौती, इसे व्यवस्थित रूप से प्लग करने के लिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करें। 6. शराब, नकदी, नशीली दवाओं और मुफ्त वस्तुओं के परिवहन के लिए संवेदनशील मार्गों का मानचित्रण।

केंद्रीय एजेंसियों को दिशा-निर्देश

1. असम राइफल्स द्वारा भारत-म्यांमार सीमा पर कड़ी निगरानी; एसएसबी द्वारा विशेष रूप से नेपाल के साथ छिद्रपूर्ण सीमा वाले क्षेत्रों में भारत नेपाल सीमा; बीएसएफ द्वारा भारत-बांग्लादेश सीमा और पश्चिमी सीमाएँ; भारत-चीन सीमा पर आईटीबीपी द्वारा और तटीय क्षेत्र वाले राज्यों में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा निगरानी की जायें। 2. असम राइफल्स राज्य पुलिस, सीएपीएफ आदि के साथ नियमित संयुक्त सुरक्षा समन्वय बैठकें आयोजित करेगी। 3. एसएसबी किसी भी अवैध गतिविधि के लिए नेपाल और बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखेगी, खासकर मतदान के 72 घंटे पहले। 4. नागरिक प्रशासन के समन्वय से नव शामिल सीएपीएफ कंपनियों के लिए क्षेत्र से परिचित करायें। 5. राज्य पुलिस के समन्वय से संयुक्त जांच चौकियां भी स्थापित करें।

संक्षिप्त समाचार

भारत बनाएगा अपना वाणिज्यिक क्रूड रणनीतिक भंडार

आपूर्ति संबंधी चुनौतियों से निपटने में मिलेगी सहायता

नई दिल्ली, एजेंसी। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक भारत क्रूड का अपना पहला वाणिज्यिक रणनीतिक भंडार बनाने की योजना बना रहा है। इस कदम से किसी भी आपात स्थिति में आपूर्ति संबंधी चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। सरकार ने देश में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार तैयार करने और उसके परिचालन के लिए विशेष इकाई इंडियन

स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लि. (आईएसपीआरएल) का गठन किया है। इस इकाई ने कर्नाटक के पादुर में 25 लाख टन भूमिगत भंडारण बनाने के लिए बोलियां मंगाईहैं।

निविदा दस्तावेज के मुताबिक, आईएसपीआरएल ने पहले चरण में तीन स्थानों पर 53.3 लाख टन का भंडारण बनाया था। ये तीन जगह आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम (13.3 लाख टन) कर्नाटक में मंगलूरू (15 लाख टन) और पादुर (25 लाख टन) हैं। दूसरे चरण के तहत, पादुर-दो में 5,514 करोड़ रुपये की लागत से वाणिज्यिक सह-रणनीतिक भूमिगत पेट्रोलियम भंडार बनाने की योजना है। इसमें जमीन के ऊपर संबंधित सुविधाएं भी शामिल है। बोलीदाताओं से कहा गया है कि वे भंडारण के निर्माण के लिए आवश्यक वित्तीय अनुदान या उस प्रीमियम/शुल्क का बताएं, जो वे प्राधिकरण को देना चाहते हैं। बोलियां जमा करने की आखिरी तारीख 22 अप्रैल है। निविदा 27 जून तक प्रदान की जाएगी। भारत अपनी जरूरतों का 85 फीसदी से अधिक क्रूड आयात करता है।

मजबूत मांग के कारण मार्च में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर साढ़े 13 वर्ष के हाई पर

नई दिल्ली, एजेंसी। मजबूत मांग के कारण मार्च में देश के सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर साढ़े 13 साल की सबसे मजबूत वृद्धि दर में से एक रही। एचएसबीसी इंडिया सविर्सिज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स फरवरी के 60.6 से बढ़कर

मार्च में 61.2 पर पहुंच गया।परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) की भाषा में सूचकांक का 50 से ऊपर रहना विस्तार को दर्शाता है जबकि 50 से नीचे रहना संकुचन को दर्शाता है। एचएसबीसी इंडिया सर्विसेज पीएमआई को एसएंडपी ग्लोबल द्वारा लगभग 400 सेवा क्षेत्र की कंपनियों के एक पैनल को भेजे गए प्रश्नावली के जवाबों से संकलित किया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है, भारत की सेवाओं का पीएमआई फरवरी में मामूली गिरावट के बाद मार्च में बढ़ा और मजबूत मांग के कारण बिक्री और कारोबारी गतिविधियों में तेजी आई। एचएसबीसी के अर्थशास्त्री इनेस लैम ने कहा, उत्पादन क्षमता का विस्तार करने के लिए सेवा प्रदाताओं ने अगस्त 2023 के बाद से सबसे तेज गति से हायरिंग में वृद्धि की।

सरकारी प्रोजेक्ट के लिए आमने-सामने हैं मुकेश अंबानी और रतन टाटा

नई दिल्ली, एजेंसी। सरकार ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इसके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन प्रमुख बोलीदाता होंगे। इसका मकसद अर्थव्यवस्था को कार्बन मुक्त करने, जीवाश्म ईंधन आयात पर निर्भरता कम करने और भारत को ग्रीन हाइड्रोजन टेक में भारत को लीडर बनाना है। इसके लिए बोली लगाने की डेडलाइन आज खत्म हो रही है। सूत्रों के मुताबिक रिलायंस, टाटा मोटर्स और आईओसी 496 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट को हासिल करने की होड़ में सबसे आगे हैं। यह नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का हिस्सा है जिसे जनवरी 2023 में 19,744 करोड़ रुपये के बजट के साथ शुरू किया गया था।

इंडस्ट्री के सूत्रों के अनुसार रिलायंस ने इसके लिए बस और ट्रक निर्माता अशोक लीलैंड और डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ साझेदारी की है। टाटा मोटर्स ने भी आइओसीएल के साथ एक कंसोर्टियम बनाया है। अशोक लीलैंड भी इसके लिए एनटीपीसी के साथ साझेदारी कर रहा है। इस बारे में रिलायंस, एनटीपीसी और आइओसीएल ने उन्हें भेजे गए सवालों का जवाब नहीं दिया। अधिकांश ऑटो कंपनियां पिछले कुछ समय से रिलायंस और एनटीपीसी जैसी ऊर्जा कंपनियों के साथ मिलकर हाइड्रोजन-ईंधन वाले ट्रकों और बसों पर पायलट प्रोजेक्ट चला रही हैं। टाटा मोटर्स और अशोक लीलैंड के प्रवक्ता तुरंत टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे। डीआइसीवी के एक प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की कि उसने परियोजना के लिए रिलायंस को लेटर ऑफ सपोर्ट दिया है।

रिलायंस को फायदा

इस प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाने वाली कंपनियों में केवल रिलायंस ही ऐसी कंपनी है जो एंड-टू-एंड सर्विस प्रोवाइडर हो सकती है। यह एच2 के निर्माण और ईंधन वितरण से लेकर एच2-संचालित वाहन चलाने तक में सक्षम है। कंपनी इलेक्ट्रोलाइजर और हरित एच2 के लिए पीएलआई योजना में भी भागीदार है। एक सूत्र ने कहा कि रिलायंस पिछले कुछ समय से न्यू एनर्जी बिजनस पर काम कर रही है और अगर वह यह बोली जीतती है तो उसे काफी फायदा होगा। इससे देश में आने वाले वर्षों में बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन का मार्ग प्रशस्त करेगा। एच2 कॉरिडोर परियोजना का उद्देश्य देश में चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोजन से चलने वाली बसों, ट्रकों और कारों को बढ़ावा देना है।

CBSE Board Exams 2024-25: Board brings changes in composition of Class 12 question paper

CBSE has introduced changes in assessment and evaluation to align with the National Education Policy (NEP) 2020. Class 11 and 12 board exams will now have more competency-based questions and fewer constructed response questions.

As per the revised guidelines, the competency-focused questions in the form of MCQs/case-based questions, source-based integrated questions or any other type in Class 11 and 12 have been increased from 40 per cent to 50 per cent. On the other hand, the constructed response questions (short answer questions/ long answer type questions, as per existing pattern) have been reduced from 40 per cent to 30 per cent in the 2024-25 academic session. The select response type questions (MCQ) remain the same (20 per cent).

However, the composition of question papers for year-end examination/ board exams (theory) for classes 9 and 10 has not seen any changes for the new academic session (2024-25). "The main emphasis of the Board was to create an educational ecosystem that would move away from rote memorization and towards learning that is focused on developing the creative, critical and systems thinking capacities of students to meet the challenges of the 21st century," CBSE stated in an official notice.

Meanwhile, the National Council of Educational Research and Training (NCERT) today announced that the new textbooks aligned with NCF-SE 2023 for Class 3 will be available by April 2024 and Class 6 by mid-May 2024. "Also 1.21 Cr copies of 2023-2024 editions for various classes are out, with more coming regularly. Buffer stock for Classes 4, 5, 9, and 11 is ready. Digital copies of all NCERT textbooks are freely available on the NCERT portal, DIKSHA, and ePathshala portal and app," NCERT said in an official post on X (formerly known as Twitter).

केन्द्रीय विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रवेश के लिए समय-सारणी जारी

इंदौर। केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा नये शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रवेश के लिए समय-सारणी जारी की गई है। जारी समय-सारणी के अनुसार कक्षा-1 के लिए पंजीकरण-ऑनलाइन के माध्यम से 01 अप्रैल से 15 अप्रैल 2024 की शाम 5 बजे तक सभी पंजीकृत विद्यार्थियों की चयनित एवं प्रतीक्षित अनंतिम सूची का प्रदर्शन 19 अप्रैल तक जारी सूची के अनुसार चयनित विद्यार्थियों के प्रवेश का आरंभ शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत चयनित, सेवा श्रेणी वरीयता क्रम श्रेणी, उपरोक्त में शामिल आरक्षित कोटे में भरी सीटों के बाद रिक्त सीट पर प्रवेश 8 मई 2024 तक शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (NCL) प्रवेश के लिए दूसरी अधिसूचना (कक्षा-ढ्ढ) यदि पर्याप्त आवेदन पत्र प्राप्त ना हुए हों तो 8 मई से 15 मई तक तथा सूची का प्रदर्शन 22 मई से 27 मई के मध्य किया जायेगा।

समस्त पंजीकृत बच्चों की सूची, प्रवेश- योग्य बच्चों की सूची, प्रवेश के लिए अंतिम चयनित बच्चों की श्रेणी- वार सूची, प्रतीक्षा-सूची व उत्तरवर्ती सूचियों को संबंधित केन्द्रीय विद्यालय के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करने के साथ- साथ विद्यालय की वेबसाइट पर देना अनिवार्य है। यदि पंजीकरण के लिए निर्धारित प्रारंभिक, अंतिम तिथि को कोई सार्वजनिक अवकाश का दिन है, तो अगला कार्य दिवस स्वीकार्य

जेएनयू में निकली फैकल्टी पदों पर वेकेंसी

रोजगार। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के फैकल्टी पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट 8 अप्रैल 2024 है इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के माध्यम से कुल 76 पदों पर कैंडिडेट्स की भर्ती होगी. ये पद असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के है। इसके लिए आपको जेएनयू की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा कुल पदों में से प्रोफेसर के 36 पद, एसोसिएट प्रोफेसर के 33 पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 7 पद हैं.योग्यता और आयु सीमा सब पद के मुताबिक है और अलग-अलग है.अप्लाई करने के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 2000 रुपये शुल्क देना होगा. आरक्षित, पीएच और महिला कैंडिडेट्स को शुल्क नहीं देना है।

भारत की इकोनामी का बज रहा डंका ! वर्ल्ड बैंक ने भी माना लोहा

नई दिल्ली, एजेंसी। वर्ल्ड बैंक ने 2024 में भारतीय इकॉनमी की वृद्धि दर 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। उसने अपने पहले अनुमान को 1.2 प्रतिशत संशोधित किया है। वर्ल्ड बैंक ने दक्षिण एशिया वृद्धि संबंधी मंगलवार को जारी अपडेटेड जानकारी में कहा कि कुल

मिलाकर 2024 में दक्षिण एशिया में वृद्धि दर 6.0 प्रतिशत मजबूत होने की उम्मीद है। यह मुख्य तौर पर भारत में मजबूत वृद्धि, पाकिस्तान और श्रीलंका के काफी हद तक पटरी पर लौटने से संभव होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जनवरी-मार्च तिमाही में अर्थव्यवस्था 8 प्रतिशत की विकास दर से बढ़ने की राह पर है। रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण एशिया के अगले दो वर्षों तक दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र बने रहने की उम्मीद है। 2025 में वृद्धि दर 6.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

इन नीतियों की जरूरत

दक्षिण एशिया के लिए वर्ल्ड बैंक के उपाध्यक्ष मार्टिन रैजर ने कहा कि दक्षिण एशिया की वृद्धि संभावनाएं अल्पावधि में बेहतर बनी हुई हैं, लेकिन नाजुक राजकोषीय स्थिति और बढ़ते जलवायु झटके चिंता का विषय हैं। वृद्धि को अधिक लचीला बनाने के लिए, देशों को निजी निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार वृद्धि को मजबूत बनाने वाली नीतियां अपनाने की जरूरत है। साउथ एशिया के लिए विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री फ्रांजिस्का ओहनसोरगे ने कहा कि साउथ एशिया अभी अपने पॉपुलेशन डिविडेंड का पूरा लाभ उठाने में विफल हो रहा है।

वह मौका गंवा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि क्षेत्र अन्य उभरते बाजारों और विकासशील इकॉनमी की तरह कामकाजी उम्र वाली आबादी के बड़े हिस्से को लगाता है, तो उसकी उत्पादन क्षमता 16 प्रतिशत बढ़ सकती है।

इनोवा और फॉर्च्यूनर बनाने वाली जापान की दिग्गज कंपनी ने भारतीय ग्राहकों से मांगी माफी

नई दिल्ली, एजेंसी। इनोवा हाइक्रॉस एमपीवी और फॉर्च्यूनर एसयूवी जैसी गाड़ियां बनाने वाली जापानी कंपनी टोयोटा ने भारतीय ग्राहकों से माफी मांगी है। कंपनी का कहना है कि उसकी गाड़ियों की डिलीवरी के लिए ग्राहकों को एक-एक साल तक इंतजार करना पड़ रहा है। डिलीवरी में इस देरी के लिए कंपनी ने अपने ग्राहकों से माफी मांगी है। कंपनी का कहना है कि वह स्थिति में सुधार के लिए काम कर रही है। कंपनी के कुछ लोकप्रिय मॉडल और उनके वेरिएंट का वेटिंग पीरियड एक साल से भी अधिक है। साथ ही ग्राहकों की शिकायत है कि बुक की गई कारों की कीमतें डिलीवरी मिलने तक बढ़ जाती है।

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर और लेक्सस ब्रांड के डिप्टी एमडी तदाशी असाजूमा ने टीओआई के साथ इंटरव्यू में कहा कि यह हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बड़ी संख्या में ग्राहकों को हमारी गाड़ियों

की डिलीवरी का इंतजार करना पड़ रहा है। मैं इसके लिए ग्राहकों से क्षमा चाहता हूं। उन्होंने कहा कि कंपनी स्थिति में सुधार के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा, हम सो नहीं रहे हैं। हमारा प्लांट सप्ताह में छह दिन तीन शिफ्ट में काम कर रहा है और 24 घंटे प्रॉडक्शन हो रहा है। हम ग्राहकों को समय पर डिलीवरी करने के लिए जितना संभव हो उतना काम करना जारी रखेंगे। भारत में टोयोटा और मारुति सुजुकी मिलकर काम कर रही हैं। लेकिन कंपनी डिमांड के अनुरूप सप्लाई करने में नाकाम रही है।

नया प्लांट

टोयोटा ने पिछले साल नवंबर में बैंगलोर में अपनी मौजूदा फैक्ट्री में एक नए प्लांट के लिए 3,300 करोड़ रुपये के नए निवेश की योजना की घोषणा की थी। लेकिन वहां से उत्पादन 2026 में ही शुरू होगा। कंपनी के पास अभी 3.4 लाख यूनिट का उत्पादन करने की क्षमता है। इसका उपयोग कंपनी अपनी वाली कारों और सुजुकी की इनविक्टो और ग्रैंड विटारा जैसे मॉडलों के उत्पादन के लिए कर रही है। टोयोटा ने भारत में अपनी मिनी एसयूवी अर्बन लॉन्च की है जो मारुति की फोनेस्क की ट्विन है। इसकी कीमत 7.7 लाख रुपये से 13 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। असाजूमा ने कहा कि कोविड के बाद की अवधि में मजबूत मांग देखने के बाद कार बाजार में 2024 में वृद्धि में मॉडरेशन देखने को मिल सकता है। इलेक्ट्रिक वाहनों की योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने कहा कि कंपनी उन पर काम कर रही है, हालांकि उसका हाइब्रिड पर जोर जारी रहेगा। भारत से निर्यात पर, उन्होंने कहा कि कंपनी ने मध्य पूर्व और अफ्रीका में वाहनों का शिपमेंट शुरू कर दिया है।

अब एसी कंपोनेंट का नहीं करना होगा आयात

नई दिल्ली, एजेंसी। गर्मी का मौसम ढंग से अभी आया भी नहीं है कि दिल्ली एनसीआर में पार चढ़ने लगा है। ऐसे में आपको मध्यमवर्गीय ही नहीं, निम्न मध्यमवर्गी लोगों के मकानों में भी एयर कंडीशनर या एसी दिखने लगा है। यही, आपको दिल्ली के कई झुग्गी-झोपड़ी इलाकों में भी एसी लगी झुग्गी दिख जाएंगी। तभी तो सरकार चाहती है कि एसी के कंपोनेंट देश में ही बने। विदेशों से इसका आयात नहीं करना पड़े। इसे बढ़ावा देने के लिए ही केंद्र सरकार की तरफ से एसी कंपोनेंट के प्रोडक्शन पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू की गई है। अभी कल ही खबर आई है कि डाइवर्सिफाइड भारतीय मैन्यूफैक्चरिंग इंटिटी अंबर ग्रुप अंबर ग्रुप को सरकार की तरफ से 15 करोड़ रुपये का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मिला है। मतलब कि सरकार ने इस स्कीम के तहत डिसबर्सल शुरू कर दिया है।

पीएलआई स्कीम की पहली किस्त

गर्मी की धमक शुरू होते ही सरकार ने एसी कंपोनेंट के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन का भुगतान शुरू कर दिया है। इसी के तहत अंबर ग्रुप को पीएलआई के रूप में 15 करोड़ रुपये मिले हैं। इस योजना का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना और देश की घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाना है। यह एम्बर एंटरप्राइजेज को योजना के तहत वितरित पीएलआई फंड की पहली किस्त है।

बढ़ रहा है रूम एसी का बाजार

पिछले कुछ साल से भारत में रूम एसी का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। तभी तो इस समय इसका बाजार करीब 90 लाख यूनिट का हो गया है। इसके पीछे मुख्य रूप से बढ़ती गर्मी के स्तर, बढ़ती आय के स्तर और अधिक विकसित जीवनशैली जैसे ट्रिगर्स को जिम्मेदार माना जा रहा है।

पीएलआई योजना टिकाऊ विकास में सहायक

इस डेवलपमेंट पर प्रतिक्रिया देते हुए, अम्बर ग्रुप के अध्यक्ष और सीईओ जसबीर सिंह ने कहा, पीएलआई योजना भारतीय उपभोक्ता टिकाऊ उद्योग को आगे बढ़ाने में सहायक रही है। इस सेगमेंट में आत्मनिर्भर भारत के सिद्धांत को साकार किया जा रहा है। अपनी शुरुआत के बाद से, इस योजना ने एसी के लिए घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा दिया है, जो 2021 में 25 प्रतिशत से बढ़कर अब तक प्रभावशाली 45 प्रतिशत हो गई है, जो इस पहल के उल्लेखनीय प्रभाव को दर्शाता है। इस पीएलआई मंजूरी के साथ, कंपनी अब वित्त वर्ष 2028 की निर्धारित समय सीमा तक एयर कंडीशनर और इसके घटकों के उत्पादन में 75 प्रतिशत स्थानीय मूल्यवर्धन हासिल करने के लक्ष्य के साथ अपनी विनिर्माण क्षमता को गहरा करने के लिए अच्छी स्थिति में है।

घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने का लक्ष्य

एसी कंपोनेंट पर पीएलआई स्कीम शुरू करने का उद्देश्य घरेलू एसी उद्योग के लिए एक गेम चेंजर रही है। सरकार ने साल 2021 में इस योजना के तहत लाभ के लिए 26 कंपनियों का चयन किया था। इस योजना को घरेलू और विदेशी दोनों कंपनियों ने अच्छी तरह से स्वीकार किया है। इस क्षेत्र में अब तक लगभग 4,000 करोड़ रुपये के अनुमोदित निवेश के मुकाबले कंपनियों ने 4,800 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है।

दो-तीन अरब अमेरिकी डॉलर के इलेक्ट्रिक कार प्लांट के लिए भारत में जगह तलाशेगी टेस्ला, रिसर्च कर रही टीम

नई दिल्ली, एजेंसी। टेस्ला मोटर्स प्रस्तावित 2-3 अरब अमेरिकी डॉलर के इलेक्ट्रिक कार प्लांट के लिए इस महीने भारत में स्थानों की तलाश करने के लिए एक टीम भेजेगी। फाइनेंशियल टाइम्स ने इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) कंपनी की योजना की जानकारी रखने वाले दो लोगों के हवाले से यह जानकारी दी। यह खबर ऐसे समय में सामने आई है, जब पिछले महीने भारत ने उन कंपनियों के लिए उच्च कीमत वाले आयातित ईवी पर टैरिफ कम करने का फैसला लिया है, जो तीन साल के भीतर देश में ईवी को बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। खबर मे टेस्ला की योजना की जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से कहा गया है कि टीम अप्रैल के अंत तक

संयंत्र स्थापित करने के लिए स्थानों का अध्ययन कर सकती है। टीम मौजूदा ऑटोमोटिव हब वाले राज्यों पर फोकस कर रही है, जिसमें पश्चिम में महाराष्ट्र व गुजरात और दक्षिण में तमिलनाडु शामिल हैं। कुछ वाहन निर्माताओं के पास नई दिल्ली के पड़ोस में हरियाणा में संयंत्र हैं।

कच्चे आम के बेशकीमती लाभ

इस मौसम में जरूर फायदा उठाएं

गर्मियों में कच्चे और पके आम की भरपूर आवक होती है और इन दोनों के अपने अलग फायदे हैं। कच्चे आम की चटनी हो या पना, गर्मी के मौसम में स्वाद और सेहत दोनों के लिए बेहद लाभदायक है। जानिए कच्चे आम यानि कैरी के यह 7 बेहतरीन फायदे

- कच्चे आम का प्रयोग सिर्फ भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए ही नहीं बल्कि स्वस्थ रहने के लिए भी किया जा सकता है। कच्चे आम के सेवन से रक्त संबंधी विकारों से बचा जा सकता है।
- अगर आपको एसिडिटी, गैस या अपच जैसी समस्या हो रही हैं, तो कच्चे आम का सेवन आपके लिए काफी लाभदायक होगा। यह कब्ज और पेट के सभी विकारों से निपटने में आपकी मदद करेगा।
- ऊल्टी आना या फिर जी मचलाने की समस्या में कच्चे आम का काले नमक के साथ सेवन करना आपको निजात दिला सकता है। कुछ ही देर में यह आपको सामान्य महसूस कराने में मदद करेगा।
- कच्चे आम का नियमित सेवन कर न केवल आप अपने बालों को काला बनाए रख सकते हैं, बल्कि बेदाग और दमकती हुई त्वचा आसानी से पा सकते हैं। इससे त्वचा में कसाव भी बना रहता है।
- शुगर की समस्या होने पर इसका प्रयोग आपके शुगर लेवल को कम करने में बेहद सहायक होगा। इसका प्रयोग कर आप शरीर में आयरन की पूर्ति भी आसानी से कर सकते हैं।
- इसमें विटामिन सी अच्छी खासी मात्रा में मौजूद है, जो आपकी खूबसूरती का ध्यान तो रखता ही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी इजाफा करता है। इसक प्रयोग आंखों के लिए भी फायदेमंद है।
- अगर आपको अत्यधिक पसीना आता है, तो कच्चे आम का पना या फिर किसी भी रूप में इसका प्रयोग आपकी इस समस्या को आसानी से दूर करने में कारगर साबित होगा।

गठिया का दर्द सोख लेती हैं ये चीजें, जड़ से खत्म होगी दर्दनाक तकलीफ

आर्थराइटिस पेन को गठिया का दर्द भी कहा जाता है। जिसे कम करने के लिए कुछ चीजों का सेवन करना चाहिए। शोधों में इन फूड्स को दर्द और इंफ्लामेशन से छुटकारा दिलाने वाला पाया गया है।

बुढ़ापे के साथ जोड़ों का दर्द भी आना आम बात है। इस रोग को गठिया या आर्थराइटिस भी कहा जाता है। उम्र के साथ घुटनों, कोहनी आदि हड्डी के जोड़ों की मूवमेंट कम होने लगती है और इंफ्लामेशन बढ़ने लगती है। जिसकी वजह से सूजन, दर्द, अकड़न जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। इस बीमारी में कुछ एंटी-इंफ्लामेटरी फूड्स रामबाण साबित हो सकते हैं। इन खाद्य पदार्थों में दर्द को कम करने वाली शक्ति होती है। इसलिए घर के बड़े-बुजुर्गों को इन चीजों का सेवन जरूर करवाएं।

सेब है गठिया का इलाज

सेब खाकर गठिया के दर्द से राहत पाई जा सकती है। क्योंकि, इसे मोटापे से आई सूजन व इंफ्लामेशन को कम करने में मददगार देखा गया है। जिससे मोटापे के शिकार लोगों में जोड़ों के दर्द में भी कमी देखी गई।

खाने में अच्छी तरह डालें अदरक और हल्दी

अदरक और हल्दी को आयुर्वेद में कई रोगों की दवा माना जाता है। क्योंकि यह एंटी-इंफ्लामेटरी गुणों का भंडार हैं। इन्हें औषधि या भोजन के रूप में लेने पर दर्द, सूजन आदि लक्षणों से राहत पाई जा सकती है।

स्ट्रॉबेरी, क्रैनबेरी, ब्लैकबेरी

सभी बेरीज में विटामिन सी और अन्य एंटीऑक्सीडेंट्स की भरमार होती है। आर्थराइटिस फाउंडेशन के मुताबिक, इनमें गठिया से लड़ने वाले गुण होते हैं।

मशरूम है लाभदायक

मशरूम के अंदर फेनोलिक, इंडोलिक, मायकोस्टेरोइड्स, फैटी एसिड, कैरोटेनोइड्स, विटामिन और बायोमेटल जैसे कई सारे एंटी-इंफ्लामेटरी कंपाउंड होते हैं। यह सभी तत्व आर्थराइटिस के इलाज में मदद करते हैं।

अनार खाने के फायदे

अनार के अंदर टैनिन काफी मात्रा में होते हैं। इनमें एंटी-इंफ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं। जो घुटनों के दर्द से राहत दिलाने में मदद करते हैं। इसलिए गठिया के मरीजों के लिए इसका सेवन फायदेमंद माना जाता है

पथरी-पीलिया के लिए नैचुरल टॉनिक है गन्ने का रस

गर्मी में ठंडक पाने के लिए अधिकतर लोग कोल्ड ड्रिंक्स या अन्य शुगरी ड्रिंक्स का अधिक सेवन करते हैं। इन चीजों के सेवन से आपकी सेहत पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। अगर आप गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने के साथ कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचने व उनका इलाज करना चाहते हैं, तो आपको गन्ने का रस पीना चाहिए। गन्ने का रस एक 100 नैचुरल ड्रिंक है जिसमें किसी तरह कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। हालांकि इसमें थोड़ा फैट, फाइबर और प्रोटीन की मात्रा होती है। गन्ने का रस में सोडियम, पोटैशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसी पोषक पाए जाते हैं। गर्मियों में बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के अलावा गन्ने का रस आपको कैंसर से बचाने, पाचन को दुरुस्त रखने, किडनी के कामकाज को बढ़ाने, हड्डियों को मजबूत बनाने और खून की कमी से बचाने आदि में सहायक है।

बॉडी को तुरंत मिलती है एनर्जी

गन्ने का रस स्वादिष्ट होता है और इसे पीने से आपके शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है। गर्मियों में पसीना और चिलचिलाती धूप शरीर की सारी ताकत खत्म कर देती है और डिहाइड्रेट कर देती है। गन्ने का ताजा रस शरीर को तरोताजा करने का हेल्दी तरीका है।

लिवर के कामकाज को बनाता है मजबूत

एक अध्ययन के अनुसार गन्ने का रस विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और यह लिवर के कामकाज को बेहतर बनाने में सहायक है। अध्ययनों से पता चलता है कि गन्ने का रस नेचर में एल्कलाइन होता है, जो शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। यही वजह है कि पीलिया होने पर गन्ने का रस पीने की सलाह दी जाती है।

कैंसर से लड़ने की क्षमता

अध्ययनों से पता चला है कि गन्ने के रस में मौजूद पॉलीफेनोल्स, हाई एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कैंसर गुण होते हैं। यही वजह है कि गन्ने के रस में कैंसर से लड़ने की क्षमता होती है।

पाचन तंत्र को बनता है मजबूत

अगर आपका पाचन तंत्र कमजोर है, तो आपको गन्ने का रस पीना चाहिए। गन्ने के रस में मौजूद पोटैशियम पेट में पीएच लेवल को संतुलित करता है। गन्ने का रस पीने से व्यक्ति हाइड्रेटेड रहता है और नियमित मल त्याग में मदद मिलती है। यह पेट के संक्रमण को रोकने में भी मदद करता है।

गर्मियों में गन्ने के जूस से बढ़िया कोई ड्रिंक नहीं है, स्वाद और पोषण से भरपूर गन्ने का रस शरीर को ऊर्जा देने के अलावा कई बीमारियों से बचाने में सहायक है।

डायबिटीज के मरीजों के लिए बढ़िया ड्रिंक

हालांकि गन्ने के रस में शुगर होती है लेकिन सीमित मात्रा में इसके सेवन से डायबिटीज के रोगियों को फायदेमंद हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, नैचुरल शुगर में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने से रोकता है। अध्ययन के अनुसार, गन्ने में विभिन्न पॉलीफेनोल्स होते हैं जो डायबिटीज को बेहतर ढंग से मैनेज करते हैं।

किडनी हेल्थ के लिए पावरफुल ड्रिंक

गन्ने के रस में बिल्कुल भी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, साथ ही इसमें सोडियम भी बहुत कम होता है। इसके अलावा इसमें सैचुरेटेड फैट भी नहीं होता है और यही वजह है कि यह किडनी को स्वस्थ रखने में मदद करता है।

यह भी हैं गन्ने का जूस पीने के फायदे

गन्ने का रस शरीर की सूजन, यूटीआई, किडनी की पथरी और प्रोस्टेटाइटिस जैसे लक्षणों को मैनेज करता है, इसमें कैल्शियम की मात्रा होने की वजह यह हड्डियों को विकास और मजबूती के लिए जरूरी है, साथ ही यह मुंह की दुर्गन्ध दूर करता है और दांतों को मजबूती देता है

गन्ने के रस के नुकसान

गन्ने के रस पीने के साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी यह कुछ स्वास्थ्य समस्याओं की वजह बन सकता है। गन्ने में पोलीकोसानॉल नामक तत्व होता है और इसके अधिक सेवन से अनिद्रा, पेट खराब, चक्कर आना, सिरदर्द और वजन कम हो सकता है। यह रक्त को पतला भी कर सकता है और रक्त में कोलेस्ट्रॉल लेवल को को प्रभावित कर सकता है।

बीमारियों से लड़ने के लिए मजबूती देती है भिंडी

गर्मियों के मौसम की एक सब्जी भिंडी जो सभी सब्जियों में खास मानी गई है। यह काफी लोगों की पहली पसंद होती है, तो कई लोग इसे नापसंद भी करते हैं। अगर आप गर्मियों में भिंडी खाते हैं तो आपका इम्युनिटी सिस्टम बेहतर होता है, भिंडी खाने से शरीर को ज्यादातर बीमारियों से लड़ने के लिए मजबूती मिलती है तथा आपकी बॉडी आसानी से वायरल इंफेक्शन से लड़ सकती है। यह इम्युनिटी बूस्ट करती है। लेडी फिंगर कही जाने वाली यह हरी सब्जी खास तौर पर यह बच्चों को अधिक पसंद आती है।

- **पाचन तंत्र**- भिंडी फाइबर से भरपूर सब्जी है। इसमें मौजूद लसलसा फाइबर पाचन तंत्र के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इससे पेट फूलना, कब्ज, दर्द और गैस जैसी समस्याएं नहीं होती।
- **हृदय**- भिंडी आपके दिल को भी स्वस्थ रखती है । इसमें मौजूद पैक्टिन कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, साथ ही इसमें पाया जाने वाला घुलनशील फाइबर, रक्त में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, जिससे हृदय रोग का खतरा कम होता है।
- **डायबिटीज**- इसमें पाया जाने वाला यूगेनॉल, डायबिटीज के लिए बेहद फायदेमंद साबित होता है। यह शरीर में शर्करा के स्तर को बढ़ने से रोकता है, जिससे डायबिटीज का खतरा कम होता है।
- **अनीमिया**- भिंडी एनीमिया में भी काफी लाभदायक होती है। इसमें मौजूद आयरन हीमोग्लोबिन का निर्माण करने में सहायक होता है, और विटामिन- के, रक्तस्त्राव को रोकने का कार्य करता है।
- **आंखों की रोशनी**- भिंडी विटामिन-ए, बीटा कैरोटीन और एंटी-ऑक्सीडेंटद्यस से भरपूर होती है, जो सेल्युलर चयापचय से उपजे मुक्त कणों को समाप्त करने में सहायक होते हैं। यह कण नेत्रहीनता के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा भिंडी मोतियाबिंद से भी बचाती है।
- **हड्डियां बनाए मजबूत**- भिंडी में पाया जाने वाला लसलसा पदार्थ हमारी हड्डियों के लिए उपयोगी होता है। इसमें पाया जाने वाला विटामिन-के हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक होता है।
- **इम्यून सिस्टम**- भिंडी में विटामिन-सी होने के साथ यह एंटीआक्सिडेंट से भरपूर होती है। जिसके कारण यह इम्यून सिस्टम को मजबूत कर शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। इसे भोजन में शामिल करने से कई बीमारियों जैसे खांसी, ठंड जैसी समस्याएं भी नहीं होती।
- **कैंसर**- भिंडी को अपनी थाली में शामिल करके आप कैंसर को दूर भगा सकते हैं। खासतौर से कोलन कैंसर को दूर करने में भिंडी बहुत फायदेमंद है। यह आंतों में मौजूद विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करती है, जिससे आंतें स्वस्थ रहती हैं और बेहतर तरीके से कार्य करती हैं।
- **वजन**- भिंडी आपके वजन को कम करने के साथ ही अपकी त्वचा को जवान बनाए रखने में भी मदद करती है। इसका प्रयोग बालों को खूबसूरत, घना और चमकदार बनाने के लिए भी किया जाता है। इसके लसलसे पदार्थ को नींबू के साथ शैंपू की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।

कोई भी बीमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। इन दिनों खराब लाइफस्टाइल और गलत खान-पान के कारण हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। हृदय को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी डाइट और व्यायाम करना बहुत ही जरुरी है। एक्सरसाइज करने से आपका शरीर एकदम फूर्तीला रहता है और आप बीमारियों से भी दूर रहेंगे। आज आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताएंगे जो आपके हार्ट के साथ-साथ आपके स्वस्थ शरीर के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगी। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में.

दिल रहेगा एकदम स्वस्थ रुटीन में ये ट्राई करें

कार्डियो एक्सरसाइज करें

हृदय को स्वस्थ रखने के लिए आप कार्डियो एक्सरसाइज को अपनी डेली रुटीन में शामिल कर सकते हैं। इसमें जॉगिंग, साइकिलिंग और वॉक भी शामिल हैं। इससे आपके हृदय की गति तेज होगी और साथ में हृदय की मांसपेशियों की भी एक्सरसाइज होगी।

स्ट्रेचिंग और वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज

आप अच्छे स्वास्थ्य और दिल को स्वस्थ रखने के लिए वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग करने से आपके शरीर में लचीलापन आता है। साथ ही वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज करने से आपका वजन कंट्रोल में रहता है और शरीर में ताकत भी आती है। वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज में आप पुशअप्स, स्क्वैट्स, पुलअप्स जैसी एक्सरसाइज को अपनी रुटीन का हिस्सा बना सकते हैं।

जंपिंग जैक एक्सरसाइज करें

जंपिंग जैक एक्सरसाइज आपके हेल्दी हार्ट के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इससे आपका हृदय स्वस्थ रहता है। इससे हृदय की गति भी बहुत अच्छे से होती है।

कैसे करें जंपिंग जैक एक्सरसाइज

.सबसे पहले आप सीधे खड़े हो जाएं।
.इसके बाद ऊपर की ओर उछलें और अपने हाथों को भी ऊपर उठा लें। .हाथ उठाने के बाद पैरों को भी फैला लें। ऐसे ही 10-15 मिनट तक करें और फिर नीचे नार्मल पॉजिशन में आ जाएं।

हर्डल जंप करें

आप हृदय को स्वस्थ रखने के लिए आप हर्डल जंप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इसमें आप किसी हर्डल को लेकर उसके ऊपर से जंप करें। आप डंबल, बॉक्य या फिर किसी स्टेपर का हर्डल के रुप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीजों को आप उछल कर पार करें। इस एक्सरसाइज से आपकी हार्ट बीट तेज होगी। हार्ट बीट तेज होने से आपका दिल मजबूत बनेगा।

बर्पी एक्सरसाइज करें

बर्पी एक्सरसाइज आपकी बाजुओं , टांगों और छाती के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इस एक्सरसाइज में स्क्वाट, पुशअप, जंपिंग तीनों चीजें एकसाथ की जाती है। यह तीनों एक्सरसाइज आपको एक सैट में ही करनी पड़ती हैं। इस एक्सरसाइज से आपकी हृदय गति तेज होगी और दिल की धड़कन एकदम नॉर्मल हो जाएगी।

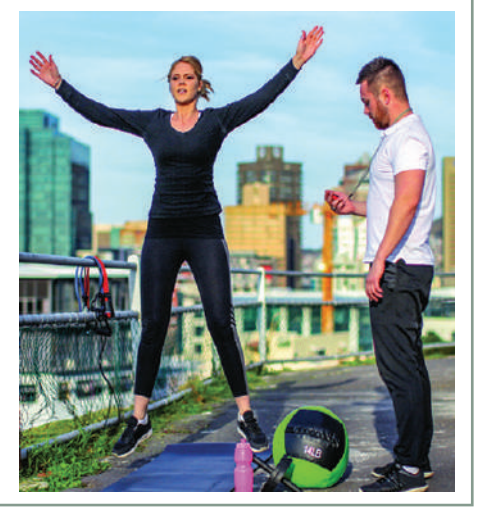

आंद्रे रसेल ने सचिन तेंदुलकर को छोड़ा पीछे, दिल्ली के खिलाफ मैच के दौरान तोड़ा रिकॉर्ड

विशाखापत्तनम, एजेंसी। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के सर्वकालिक रन-स्कोरिंग चार्ट में महान भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है। 35 वर्षीय खिलाड़ी ने विशाखापत्तनम में दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के खिलाफ आईपीएल मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। खेल के दौरान रसेल ने एक बार फिर अपनी पुरानी पावर-हिटिंग दिखाई और केवल 19 गेंदों में 41 रन बनाए जिसमें चार चौकों और तीन छक्कों के साथ उनका स्ट्राइक रेट 215 से ज्यादा का रहा।

रसेल ने अपने आईपीएल करियर में 115 मैचों में 29.96 की औसत, 11 अर्धशतक और 176.11 की स्ट्राइक रेट के साथ 2,367 रन बनाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 88* है। वह आईपीएल में अब तक के 44वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। इस सीज़न में तीन मैचों में ऑलराउंडर ने 105.00 की औसत से 105 रन बनाए हैं जिसमें 238 से अधिक की स्ट्राइक रेट है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 64* है। 2019 सीजन रसेल के बल्ले से सर्वश्रेष्ठ था जब उन्होंने 14 पारियों में 56.66 की औसत और 204 से अधिक की स्ट्राइक रेट से चार अर्धशतकों के साथ 510 रन बनाए। वहीं सचिन ने 2008-13 तक मुंबई इंडियंस के लिए 78 आईपीएल मैच खेले जिसमें 34.83 की औसत और 119 से अधिक की स्ट्राइक रेट के साथ 2,334 रन बनाए। उन्होंने अपने करियर में एक शतक और 13 अर्द्धशतक बनाए जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 100* था। 2010 में उन्होंने 15 मैचों में 47.53 की औसत और 132 से अधिक की स्ट्राइक रेट से पांच अर्द्धशतक के साथ 618 रन बनाकर सर्वाधिक रनों के लिए ऑरेंज कैप जीती।

मैच की बात करें तो विशाखापत्तनम के मैदान पर दिल्ली कैपिटल्स को अपने आईपीएल इतिहास की शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। कोलकाता ने पहले खेलते हुए सुनील नेरेन के 39 गेंदों पर 85, रघुवंशी के 27 गेंदों पर 54, आंद्रे रसेल के 19 गेंदों पर 41, रिंकू सिंह के 8 गेंदों पर 26 रनों की बदौलत 7 विकेट खोकर 272 रन बनाए थे। जवाब में दिल्ली ने पावरप्ले में ही शॉ, वार्नर, मार्श के विकेट गंवा लिए। कप्तान पंत और ट्रिस्टन स्टब्स ने अर्धशतक लगाए लेकिन टीम लक्ष्य से बहुत दूर रह गई और 106 रन से मैच गंवा लिया। इस हार के साथ ही दिल्ली अंक तालिका में आखिरी पायदानों पर आ गई है तो वहीं, कोलकाता 3 मैचों में 3 जीत के साथ पहले नंबर पर आ गई है।

आईपीएल 2024

अपनी पहली ही पारी में तोड़ दिया 16 साल पुराना रिकॉर्ड

18 साल के बल्लेबाज ने रचा इतिहास

विशाखापट्टनम, एजेंसी। कोलकाता नाईट राइडर्स ने आईपीएल 2024 के 16वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 20 ओवर में 272 रन बनाने का कारनामा किया। इस दौरान 18 साल के बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी ने काफी महफिल लूटी। अंगकृष रघुवंशी भले ही आईपीएल में पहली बार बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा से सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने अपनी पहली आईपीएल पारी में ही लीग के 16 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया।

18 साल के बल्लेबाज ने रचा इतिहास

अंगकृष रघुवंशी ने इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 27 गेंद का सामना करते हुए पांच चौके और तीन छक्कों की मदद से 54 रन बनाए। इसी के साथ अंगकृष रघुवंशी आईपीएल के इतिहास में करियर की पहली पारी में अर्धशतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। अंगकृष ने 18 साल, 303 दिन की उम्र में ये कारनामा किया। इससे पहले ये रिकॉर्ड श्रीवत्स गोस्वामी के नाम था। श्रीवत्स गोस्वामी ने साल 2008 में 19 साल 1 दिन की उम्र में अपनी आईपीएल की पहली पारी में अर्धशतक लगाया था।

इस लिस्ट में भी निकले सबसे आगे

अंगकृष ने 25 गेंद पर अपना पहला आईपीएल अर्धशतक जड़ा। इसी के साथ अंगकृष रघुवंशी 200 स्ट्राइक रेट के साथ आईपीएल अर्धशतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए। वहीं, ये आईपीएल करियर की पहली पारी में बनाया गया दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है। इससे पहले 2008 में जेम्स होप्स ने अपनी पहली आईपीएल पारी में 24 गेंद में फिफ्टी लगाई थी।

अंगकृष रघुवंशी को ऑक्शन में मिली इतनी रकम

कोलकाता नाईट राइडर्स ने आईपीएल 2024 के ऑक्शन में अंगकृष रघुवंशी को 20 लाख रुपये देकर अपनी टीम में शामिल किया था। बता दें, अंगकृष रघुवंशी के बचपन के कोच अभिषेक नायर हैं, जो केकेआर की टीम के सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा हैं।

इसके अलावा अंगकृष ने भारत के लिए अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 भी खेला था। इस वर्ल्ड कप में वह टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। उन्होंने छह पारियों में 278 रन बनाए थे।

मिनर्वा एकेडमी ने सब-जूनियर लीग में नामधारी को रिकॉर्ड तोड़ 33-1 स्कोर से हराया

चंडीगढ़, एजेंसी। मिनर्वा के युवा खिलाड़ियों ने ऐसा मैच खेला जो इतिहास की किताबों में दर्ज हो जाएगा। मिनर्वा एकेडमी ने शुद्ध प्रभुत्व का प्रदर्शन करते हुए सब जूनियर लीग 2023-24 में नामधारी एकेडमी को 33-1 के बड़े स्कोर से हराया। मैच के पहले मिनट से लेकर अंतिम सीटी बजने तक मिनर्वा के प्रतिभाशाली अंडर-13 खिलाड़ियों की ओर से गोलों की बारिश होती रही। पहले हाफ में आश्चर्यजनक 16 गोल हुए और दूसरे हाफ में अविश्वसनीय 17 गोल के साथ मिनर्वा एकेडमी ने अपने विरोधियों को स्तब्ध कर दिया। वे पूरी ताकत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए मैदान पर गोल दागते रहे। मिनर्वा की अगुवाई करते हुए उनके युवा सितारों ने शानदार प्रदर्शन किया।

टोनी ने हैट्रिक के साथ आक्रमण की शुरुआत की और उन्होंने साबित कर दिया कि वे किस स्तर के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा मतेई ने 4 गोल के साथ अपनी गोल स्कोरिंग क्षमता का प्रदर्शन किया, जबकि चेतन सिंह ने एक ही गेम में प्रभावशाली 6 गोल करके अपनी क्लास दिखा दी। स्थानापन्न खिलाड़ियों ने भी खेल पर अपनी छाप छोड़ी। आकाश युमनाम और ममेश लैशराम ने बेंच से आकर 1-1 गोल किया। मैच का सबसे बड़ा हीरो डेनामोनी था, जिसने डबल हैट्रिक के साथ 8 गोल दागकर सभी का ध्यान अपनी ओर कर दिया।

कप्तान आजम खान ने भी शानदार 9 गोल करके मिनर्वा की जीत को जोरदार तरीके से मजबूत करते हुए उपस्थिति दर्ज कराई। यह अविस्मरणीय जीत न केवल मिनर्वा एकेडमी की युवा टीम में असाधारण प्रतिभा और गहराई को उजागर करती है, बल्कि उत्कृष्टता और सफलता की उनकी निरंतर खोज का एक स्पष्ट संदेश भी देती है। इस तरह के आक्रामक युवा खिलाड़ियों के साथ मिनर्वा एकेडमी अपनी जीत की राह जारी रखने और युवा फुटबॉल की दुनिया को हिला देने के लिए तैयार है।

पंत पर लगातार दूसरे मैच में जुर्माना लगा स्लो ओवर रेट के लिए 24 लाख का फाइन

विशाखापट्टन, एजेंसी। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत पर लगातार दूसरे मैच में जुर्माना लगा है। उन्हें कोलकाता नाइटराइडर्स (चयक्र) के खिलाफ स्लो ओवर रेट का दोषी पाया गया। इसके लिए उन पर 24 लाख रुपए का फाइन लगाया गया। इंडियन प्रीमियर लीग ने यह जानकारी गुरुवार को दी। इससे पहले, चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ हुए पिछले मैच में भी वे स्लो ओवर रेट के दोषी पाए गए थे। लेकिन सीजन की पहली गलती होने की वजह से 12 लाख का फाइन लगाया गया था। पंत के अलावा दिल्ली कैपिटल्स के इम्पैक्ट प्लेयर सहित प्लेइंग-11 का हिस्सा रहे खिलाड़ियों पर मैच फीस का 25त जुर्माना लगा है। विशाखापट्टनम के डॉ. वाईएस राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में कोलकाता ने टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 272 रन बनाए। जवाबी पारी में दिल्ली की टीम 17.2 ओवर में 166 रन पर ऑलआउट हो गई।

इंदौर जिला सब जूनियर - मिनी रैंकिंग बैडमिंटन स्पर्धा

सोम्या, मायरा, दिव्यांशी, तविशा, आरवराज, हर्षवर्धन, अनवित और काव्य को खिताब

इंदौर। इंदौर जिला बैडमिंटन संगठन के तहत ऐरेना बैडमिंटन क्लब और इंदौर बैडमिंटन एकेडमी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित पहली एरेना -आईबीए ट्राफी इंदौर जिला सब जूनियर-मिनी रैंकिंग बैडमिंटन स्पर्धा में हर्षवर्धन सिंह राजपूत ने 9 वर्ष, अनवित गोयल ने 11 वर्ष, आरवराज सिंह बग्गा ने 13 वर्ष और काव्य शर्मा ने 15 वर्ष बालक वर्ग के खिताब जीते। तविशा यादव ने 9 वर्ष, मायरा भार्गव ने 11 वर्ष, सोम्या वर्मा ने 13 वर्ष और दिव्यांशी गांधी ने 15 वर्ष बालिका खिताब हासिल किया।

एरेना -आईबीए क्लब में हुई इस स्पर्धा में 13 वर्ष बालिका फाइनल में सोम्या वर्मा ने अनन्या शारदा को 18-21, 21-18, 21-13 से हराया। 11 वर्ष बालिका फाइनल में मायरा भार्गव ने ओमिशा मेहता को 21-17, 21-8 से पराजित किया। 15 वर्ष बालिका फाइनल में दिव्यांशी गांधी ने पहले क्रम की अर्ना बतरा को 21-16, 23-21 से हराया। 9 वर्ष बालिका फाइनल में तविशा यादव ने ऐजा बेग को 21-9, 21-5 से पराजित किया। 9 वर्ष बालक फाइनल में हर्षवर्धन सिंह राजपूत ने रुद्र मित्तल को 27-25, 21-17 से और 11 वर्ष बालक फाइनल में अनवित गोयल ने शाश्वत त्रिपाठी को 21-4, 21-15 से पराजित किया। 13 वर्ष बालक फाइनल में आरव राज सिंह बग्गा ने शोभित गुप्ता को 21-9, 21-3 से हराया। 15 वर्ष बालक फाइनल में काव्य शर्मा ने प्रफुल्ल पाठक को 19-21, 21-13, 21-18 से पराजित किया।

निवृत्त पुलिस अधिकारी (एसीपी) संतोष कुमार तोमर, समाजसेवी वीरेंद्र सिंह तोमर और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के निवृत्त मुख्य उप महाप्रबंधक विजय रांगणेकर ने पुरस्कार वितरण किया। इंदौर जिला बैडमिंटन संगठन सचिव आरपी सिंह नैयर और सह सचिव धर्मेश यशलहा, एरेना क्लब की सीईओ रुचिरा कुलकर्णी, सुधांशु व्यास, रजनीश जैन, सत्येंद्र होल्कर भी मौजूद थे। स्पर्धा संबंधित जानकारी मुख्य निर्णायक धर्मेश यशलहा ने दी। स्पर्धा सचिव सत्येंद्र होल्कर ने संचालन किया। प्रतीक गुजराती ने आभार व्यक्त किया। स्पर्धा के मुख्य निर्णायक धर्मेश यशलहा और अंपायरों को भी सम्मानित किया गया।

डूबती हुई मुंबई इंडियंस को सूर्यकुमार का सहारा

नई दिल्ली, एजेंसी। मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजी क्रम को जल्द ही मजबूती मिलेगी क्योंकि दुनिया के नंबर एक टी20 बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) में लगभग सभी फिटनेस टेस्ट पास कर लिये हैं। वह सत्र का अपना पहला आईपीएल मैच खेलने के करीब हैं। सूर्यकुमार की टखने में ग्रेड दो चोट के लिए और स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी हुई थी।

कब से चोटिल चल रहे सूर्यकुमार यादव

उन्होंने आखिरी मुकाबला दक्षिण अफ्रीका में टी20 सीरीज में खेला था। बीसीसीआई के एक वरिष्ठ सूत्र ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर पीटीआई को बताया, 'सूर्या ने एक नियमित परीक्षण को छोड़कर बाकी सभी परीक्षण पास कर लिए हैं जो एनसीए से आरटीपी (खेलने के लिए वापसी) प्रमाण पत्र पाने के लिए अनिवार्य हैं। एक और परीक्षण होना बाकी है जिसके बाद स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी।'

उन्होंने कहा, 'वह आराम से बल्लेबाजी कर रहा है।' यह पूछे जाने पर कि क्या सूर्यकुमार 7 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस का घरेलू मैच खेल पाएंगे तो सूत्र ने कहा, 'कल के परीक्षणों के बाद स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी। अगले मैच से पहले अब भी तीन दिन हैं। लेकिन वह लंबे समय बाद वापसी कर रहा है इसलिए ऐसा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 11 अप्रैल को होने वाले घरेलू मैच के दौरान भी हो सकता है। यह स्टार बल्लेबाज पिछले चार से पांच सीजन में मुंबई के लिए सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी रहा है और इस सीजन में अपने पहले तीन मैच हारने वाली टीम को उनकी कमी खल रही है। सूर्यकुमार के स्थान पर आए पंजाब के खिलाड़ी नमन धीर अभी तक लय में नहीं आ पाए हैं और कप्तान हार्दिक पंड्या को निश्चित रूप से इस स्थिति से निपटने के लिए उनकी जरूरत होगी। जहां तक बीसीसीआई की चिकित्सा टीम का सवाल है तो स्पष्ट आदेश यह सुनिश्चित करना था कि भारत का प्रमुख टी20 बल्लेबाज अमेरिका और वेस्टइंडीज में टी20 विश्व कप के लिए पूरी तरह से फिट रहे और यह भी सुनिश्चित करना था कि आईपीएल के दौरान वह चोटिल नहीं हों।

तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई काइली जेनर!

टिमोथी संग करेंगी पहले बच्चे का स्वागत

अमेरिकी सोशलाइट काइली जेनर ने कॉस्मेटिक्स की दुनिया में अपना नाम बनाया है। काइली ने अपने एक्स पार्टनर ट्रैविस स्कॉट संग स्टॉर्मी और ऐरे का स्वागत किया था। ट्रैविस स्कॉट के अलग होने के बाद काइली की लाइफ में एक्टर टिमोथी चालमेट की एंट्री हुई। वहीं अब खबरें आ रही हैं कि काइली टिमोथी चालमेट के बच्चे की मां बनने वाली हैं। जी हां...आपने ठीक सुना। एक लोकप्रिय अमेरिकी कॉमेडियन एक्टर डैनियल तोश ने दावा किया है कि लवबर्ड्स का इली और टिमोथी अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाले हैं। तोश ने दावा किया, यहाँ कुछ बहुत क्रेजी है। मैं मालिबू में एक ग्रॉसरी शॉप पर गया, और मैं वहां एक कर्मचारी से बात कर रहा था। मैं इससे बचने की कोशिश करता हूं लेकिन मैं इस आदमी से बात कर रहा था, और मैंने कहा, आप लोग कल क्यों बंद थे? वह कहता है, ठीक है, मुझे इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन कीपिंग अप विद द कार्दशियन, शो , कल यहां अपने सीज़न के एंड की शूटिंग कर रहे थे।

रूपाली को महंगा पड़ा महिला डॉक्टर को अपशब्द कहना

'अनुपमा' फेम रुपाली गांगुली के फैंस उनके खासा नाराज हैं। लोग उन्हें एक आदर्श महिला के रूप में देखते हैं और उनसे कुछ भी अपशब्द की उम्मीद नहीं करते। लेकिन अपने एक इंटरव्यू में रुपाली ने कुछ ऐसा कह दिया, जिससे लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। रुपाली गांगुली को 'अनुपमा' के लिए हर घर में प्यार मिलता है। लेकिन इस वक्त फैंस उनसे नाराज हैं। दरअसल एक्ट्रेस ने एक महिला डॉक्टर के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल किया था। एक इंटरव्यू में रुपाली से ट्रोलिंग को लेकर सवाल किया गया था, जिसपर उन्होंने कहा था कि उन्हें लोग बहुत ट्रोल करते हैं और उन्हें इस बात का बुरा लगता है कि ट्रोल्स में महिलाएं ज्यादा हैं। उन्होंने कहा था, औरतों के पास इतना वेला टाइम कहां से आता है? कोई एक डॉक्टर है, ब्लडी सम गाइनैक। वो मुझे गाली देती रहती है। तेरे पास मरीज नहीं है क्या भाई? नहीं है तो बोल भेजती हूं मैं तेरे पास। काम में बिजी होजा कहां दिमाग लगा रही है। मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग कहां से दिमाग लगा रहे हैं? रुपाली गांगुली को डॉक्टर का अपमान करने के लिए ट्रोल किया जा रहा है।

शादी के 5 साल बाद प्रेग्नेंट हैं

एक्ट्रेस आरती छाबड़िया

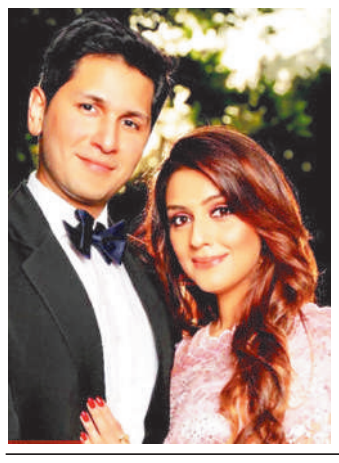

बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस आरती छाबड़िया शादी के पांच साल बाद मां बनने वाली हैं। पति विशारद बीडासी के साथ वो अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रही हैं। एक्ट्रेस ने साल 2019 में विशारद से अरेंज मैरेज की थी। वो आवारा पागल दीवाना और तुमसे अच्छा कौन है जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। फिल्मों की जानी-मानी एक्ट्रेस आरती छाबड़िया भले ही लंबे समय से बड़े पर्दे से गायब हैं लेकिन वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपने फैंस के साथ अपनी पर्सनल लाइफ की खबरें शेयर करती रहती हैं। शादी के पांच साल बाद एक्ट्रेस मां बनने के लिए तैयार हैं। उनकी उम्र फिलहाल 41 साल है और वो अपने पति विशारद बीडासी के साथ अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाली हैं। इस कपल ने 23 जून, 2019 को शादी की थी।

आयुष की रुसलान की रिलीज के लिए निर्माताओं ने एनएच स्टूडियोज से मिलाया हाथ

आयुष शर्मा की अपकमिंग एक्शन-थ्रिलर रुसलान को दुनिया भर में रिलीज करने के लिए निर्माताओं ने एनएच स्टूडियोज के साथ हाथ मिलाया है। एक्टर आयुष शर्मा ने इस साझेदारी के बारे में बात करते हुए कहा कि फिल्म निर्माण के बाद डिस्ट्रीब्यूशन काफी अहम भूमिका अदा करता है। एनएच स्टूडियोज अपने शानदार ट्रैक रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है। यह पिंक, शिवाय, अक्टूबर, ट्यूबलाइट और जब हैरी मेट सेजल जैसी कुछ सबसे मशहूर फिल्मों से जुड़ा रहा है।

संक्षिप्त समाचार

चिंटल पैराडाइसो के असुरक्षित टावर होंगे जमींदोज?

नईदिल्ली, एजेंसी। गुरुग्राम के सेक्टर 109 स्थित चिंटल पैराडाइसो के असुरक्षित टावर को तोड़फोड़ शुरू होने के बाद आठ महीने के अंदर जमींदोज कर दिए जाएंगे। यह रूपरेखा ट्विटन टावर को जमींदोज करने वाली एडिफिस कंपनी ने चिंटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी है। बिल्डर ने इससे जिला प्रशासन को अवगत करवाते हुए इन टावर को गिराने की मंजूरी देने का आग्रह किया है। वहीं, दूसरी तरफ जिला प्रशासन के पास फायर विभाग, नगर निगम, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से तोड़फोड़ को लेकर नियम और सुझाव आ गए हैं, जिन्हें एक सप्ताह के अंदर अंतिम रूप देकर शर्तों के आधार पर मंजूरी प्रदान की जाएगी। एडिफिस कंपनी की योजना के मुताबिक 15 अप्रैल से इन टावर को गिराने का काम शुरू किया जाएगा। डी, ई, एफ, जी और एच टावर के दरवाजे, खिड़कियां, बिजली तारों के अलावा टूटियों और पाइप को निकालने में 60 दिन का समय लगेगा। एक मई से ऊपरी मंजिल पर बने पानी के टैंक और छत को तोड़ा जाएगा। इसमें 90 दिन का समय लगेगा। इसके बाद एक जून से हाई रिच मशीन के माध्यम से तोड़फोड़ शुरू कर दी जाएगी, जिसमें 120 दिन का समय लगेगा। 20 जून से छोटी मशीन के साथ इन टावर को गिराने का काम शुरू होगा। इसमें 150 दिन का समय लगेगा। नींव को निकालने में 90 दिन का समय लग जाएगा। 20 जुलाई से मलबा उठाना शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें 150 दिन लग जाएंगे।

दस दिन में 10 छात्राएं डूसू की अध्यक्ष बनेंगी, दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रसंघ ने लिया फैसला

नईदिल्ली, एजेंसी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ नवरात्रि पर दस दिन के लिए दस छात्राओं को डूसू अध्यक्ष के रूप में काम करने के लिए नियुक्त करेगा। शुक्रवार को नामों की घोषणा की जाएगी। पहली छात्रा नौ अप्रैल को बतौर डूसू अध्यक्ष एक दिन के लिए कार्यभार संभालेगी। डूसू अध्यक्ष तुषार डेढ़ा ने इस बारे में एक वीडियो भी जारी किया है। इसमें कहा गया है, यह नारी शक्ति को सशक्त करने की दिशा में एक कदम है। नवरात्रि के प्रत्येक दिन नारीशक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक महिला डूसू अध्यक्ष के रूप में इसकी कमान संभालेंगी। हमने छात्र राजनीति में महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए यह पहल की है। उन्होंने कहा कि एक दिवसीय डूसू अध्यक्षों के पास अध्यक्ष की सभी शक्तियां होंगी और उन्हें पद पर रहते हुए छात्रों से संबंधित निर्णय लेने की अनुमति होगी। वर्तमान में डीयू छात्र संघ के चार सदस्यीय पैनल में केवल एक महिला अपराजिता को सचिव नियुक्त किया गया है। संघ के अन्य तीन पदों पर तुषार डेढ़ा अध्यक्ष, अभि दहिया उपाध्यक्ष और सचिन बैसला संयुक्त सचिव हैं। 'विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं की भूमिका' विषय पर एक प्रतियोगिता कराई जाएगी। इसके जरिए दस महिला डूसू अध्यक्षों के नाम चुने जाएंगे। ज्ञात हो कि आठ मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रतियोगिता के लिए छात्राओं से आवेदन मांगे गए थे। इसमें 5,000 से अधिक छात्राओं ने भाग लिया, जिनमें से 500 उम्मीदवारों को डूसू की एक टीम द्वारा शॉर्टलिस्ट किया गया।

गाजियाबाद: राम मंदिर आंदोलन के बाद से भाजपा का दुर्ग, राजनाथ भी जीत चुके हैं

नईदिल्ली, एजेंसी। वीआईपी सीट गाजियाबाद पर हर दल की नजर रहती है। पंडित जवाहर लाल नेहरू के करीबी कृष्ण चंद्र शर्मा यहां से वर्ष 1952 में चुनाव लड़े तो राजनाथ सिंह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए गाजियाबाद से सांसद चुने गए। पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल (सेवानिवृत्त) वीके सिंह रिकॉर्ड मतों से दो बार यहां से संसद पहुंचे। 1989 में समाजवादी नेता केसी त्यागी यहां से जीते थे। हालांकि, राज बब्बर और शाजिया इल्मी के हिस्से हार आई। पहले आम चुनाव में गाजियाबाद के लोगों ने मेरठ लोकसभा के लिए मतदान किया था। वर्ष 1957 के आम चुनाव में नई सीट हापुड़ के लिए वोट डाले गए।

वर्ष 2008 में परिसीमन के बाद यह सीट गाजियाबाद के नाम से जानी जाने लगी। पहले यह सीट कांग्रेस का गढ़ रही, मगर राम मंदिर आंदोलन के बाद भाजपा का मजबूत दुर्ग बन गई। वर्ष 1991 से अब तक हुए आठ चुनाव में सात बार यहां से भाजपा जीती। बसपा व सपा इस सीट से खाता नहीं खोल पाई हैं, जबकि कांग्रेस पांच बार जीती। इस बार भाजपा ने अतुल गर्ग, कांग्रेस ने डॉली शर्मा व बसपा ने नंद किशोर पुंडीर को प्रत्याशी बनाया है। लोनी, धौलाना विधानसभा जुड़ीं वर्ष 2008 में परिसीमन के बाद हापुड़ सीट गाजियाबाद के नाम से जानी जाने लगी। हापुड़ सीट में हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर, मोदीनगर, मुरादनगर और गाजियाबाद विधानसभा आती थी। परिसीमन के बाद गाजियाबाद लोकसभा में गाजियाबाद, साहिबाबाद, मुरादनगर, लोनी और धौलाना विधानसभा के मतदाता मतदान करते हैं। मोदीनगर विधानसभा गाजियाबाद जिले का हिस्सा है मगर यहां के मतदाता बागपत लोकसभा सीट के लिए मतदान करते हैं। इसी तरह धौलाना विधानसभा हापुड़ जिले में है मगर यहां के वोटर गाजियाबाद सीट का सांसद चुनते हैं। कांग्रेस ने राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉली शर्मा पर फिर से भरोसा जताया है। डॉली ने पिछले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, मगर वह तीसरे नंबर पर रही थीं। वह 2017 में कांग्रेस के टिकट पर मेयर चुनाव लड़ चुकी हैं। भाजपा ने स्थानीय विधायक अतुल गर्ग पर दांव लगाया है। अतुल के पिता डीसी गर्ग गाजियाबाद के पहले महापौर रह चुके हैं। वह दो बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। पहले टर्म में अतुल राज्य सरकार में मंत्री भी रहे। बसपा ने 29 मार्च को कारोबारी अंशय कालरा को प्रत्याशी बनाया था, मगर एक अप्रैल को उनका टिकट काटकर मुजफ्फरनगर के कारोबारी नंद किशोर पुंडीर को प्रत्याशी बना दिया गया। पुंडीर पहले भाजपा में थे।

हमारे 37 हजार करोड़ दिला दो, केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई तमिलनाडु की स्टालिन सरकार

नईदिल्ली, एजेंसी। तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार पर प्राकृतिक आपदा राहत कोष को रोकने का आरोप लगाया है। साथ ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली द्रमुक सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। अपनी याचिका में स्टालिन सरकार ने आरोप लगाया है कि प्राकृतिक आपदाओं के लिए केंद्र से मिलने वाला धन उसके लिए जारी नहीं किया जा रहा है। साथ ही इसमें तमिल सरकार ने हाल ही में आई बाढ़ और चक्रवात मिचौंग से हुए नुकसान के लिए केंद्र को 37,000 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता प्रदान करने का निर्देश देने का आग्रह किया। इतना ही नहीं याचिका में केंद्र को अंतरिम उपाय के रूप में दो हजार करोड़ रुपये जारी करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।

दिल्ली में निजी स्कूलों में 20 फीसदी तक फीस बढ़ी, बस के किराये में भी इजाफा

नईदिल्ली, एजेंसी। निजी स्कूलों में नया सत्र शुरू होने से अभिभावकों की जेब पर बोझ बढ़ गया है। कई स्कूलों ने फीस से लेकर परिवहन शुल्क में 20 फीसदी तक की बढ़ोतरी की है। अभिभावकों को महंगी दर पर किताबें खरीदनी पड़ रही है। साथ ही वर्दी खरीद के लिए दबाव बनाया जा रहा है। द्वारका निवासी प्रवीन माधव का बेटा कक्षा छठीं का छात्र है और एक नामी स्कूल में पढ़ता है। पिछले वर्ष की तुलना में उनके बच्चे का स्कूल खर्चा 1500 रुपये अधिक बढ़ गया है। प्रवीन ने बताया कि स्कूल ने ट्यूशन फीस, वार्षिक और विकास शुल्क को मिलाकर कुल फीस में 9.5 फीसदी की वृद्धि की है। परिवहन शुल्क में दस फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि फीस बढ़ाने के लिए अनुमति लेनी होती है, लेकिन स्कूल ने नए सत्र की फीस बढ़ा दी है। स्कूल सरकारी एजेंसी की ओर से आवंटित जमीन पर संचालित होता है। वहीं, मौजपुर निवासी रमेश कुमार ने कहा उनका बेटा कक्षा सातवीं में पढ़ता है। स्कूल से बच्चे का पाठ्यक्रम 7900 रुपये में मिला।

मां-बेटी ने खाया जहर, पिता ने घर में खुद को लगा ली आग

नईदिल्ली, एजेंसी। गाजियाबाद के मुरादनगर के गांव रेवड़ा रेवड़ी में दंपति और उनकी दो साल की पुत्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, गृह क्लेश के चलते महिला ने पुत्री को जहर देकर खुद भी खा लिया। पत्नी और बेटी की मौत की सूचना मिलते ही पति ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। 23 वर्षीय अंकुर कुमार, 22 वर्षीय पत्नी निशा और दो वर्षीय पुत्री शालू संयुक्त परिवार में रहते थे। अंकुर खेती करता था। ग्रामीणों ने बताया कि सोमवार देर रात करीब एक बजे अंकुर के कमरे से चीखने की आवाज आई।

आग की लपटों में घिरा अंकुर चिल्लाते हुए बाहर की ओर भाग रहा था। परिजनों ने पड़ोसियों की मदद से अंकुर की आग बुझाई। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं, घर के कमरे में निशा और उनकी पुत्री शालू बेसुध पड़ी थी और मुंह से झाग निकल रहा था। मंगलवार सुबह सात बजे मां-बेटी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।

संजय सिंह मंच से झूम कर गाने लगे इंकलाब वाला गाना, खूब बजीं तालियां

नईदिल्ली, एजेंसी। 181 दिन से तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह बुधवार रात 8 बजकर 15 मिनट पर बाहर आए। तिहाड़ से वह सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। वहां उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। उन्होंने पैर छूकर सुनीता से आशीर्वाद भी लिया। सीएम हाउस से वह सीधा आप कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। अपने स्पीच के अंत में संजय सिंह ने झूमते हुए इंकलाब वाला एक गाना भी गाया। इस दौरान मंच पर मौजूद सभी आप नेता उनके साथ वह गीत गुनगुनाने लगे। तिहाड़ से आजाद हुए संजय सिंह ने मंच से ताली बजाते हुए गाया, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब हैं, हर शहीद, हर गरीब का हमीं तो ख्वाब हैं, रुके न जो, झुके न जो... इस दौरान मंच पर मौजूद सभी नेता उनके साथ यह गीत

गाने लगे। वहां मौजूद लोग तालियां बजाने लगे। तिहाड़ से निकलते ही संजय सिंह सबसे पहले जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलने अपने परिवार के साथ सीएम हाउस पहुंचे। उन्होंने पैर छूकर सुनीता का आशीर्वाद लिया जिसके बाद सुनीता ने उन्हें गले लगाया। इस मुलाकात के दौरान संजय सिंह भावुक दिखे। इससे कुछ ही देर पहले तिहाड़ के सामने उन्होंने कहा कि यह जश्न मनाने का समय नहीं बल्कि संघर्ष का समय है। संजय सिंह के तिहाड़ से बाहर निकलने के बाद आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, देखिए... बहुत लोगों को लगता था कि संजय सिंह जी छह महीने जेल में रहे हैं तो अब उनकी आवाज दब जाएगी। संजय सिंह बाहर आए हैं, ऐसा लगता है कि शेर घायल होकर और ज्यादा खूंखार हो गया है। आखिरी में उन्होंने दिल्ली की जनता से कहा कि जेल का जवाब वोट से देना है।

पौलैंड में रूसी सैनिकों के स्मारकों को तोड़ने पर रूस ने जताई आपत्ति, विदेश मंत्रालय ने कहा- यह शर्मनाक

मॉस्को , एजेंसी। पोलैंड में रूसी सैनिकों के करीब 465 स्मारकों को नष्ट कर दिया गया है, जिसे रूसी विदेश मंत्रालय ने शर्मनाक करार दिया है। मंत्रालय ने कहा कि पोलैंड सरकार की इस कार्रवाई ने द्वितीय विश्व युद्ध की स्मृति को मिटाने का प्रयास किया है। गौरतलब है कि पिछले दो साल से भी अधिक समय से यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है, जिसमें में हजारों लोगों की मौत हो गई है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखने का विरोध करते हुए पोलैंड ने यह कार्रवाई की है।

रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि पोलैंड में हमारे वीर सैनिकों के 465 स्मारकों को नष्ट कर दिया गया है। यह शर्मनाक है। द्वितीय विश्व युद्ध और पोलिश राष्ट्र को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले 6,00,000 सोवियत सैनिकों की स्मृति को मिटाने का एक शर्मनाक कार्य है। पहले भी ऐसी कार्रवाई कर चुका है पोलैंड इससे पहले 2022 में भी, द्वितीय

विश्व युद्ध के मास्को के प्रभुत्व के प्रतीकों को हटाने के लिए पोलैंड में लाल सेना के सैनिकों के चार कम्युनिस्ट-युग के स्मारकों को नष्ट कर दिया गया था। श्रमिकों ने पोलैंड भर में चार अलग-अलग स्थानों पर स्मारकों को नष्ट करने के लिए ड्रिल और भारी उपकरणों का इस्तेमाल किया था। गौरलतब है कि 1989 में कम्युनिस्ट शासन खत्म करने के बाद से, पोलैंड सार्वजनिक स्थानों से मास्को के अतीत के प्रभुत्व के प्रतीकों, स्मारकों और पट्टिकाओं को हटा रहा है।

बाइडन को पीछे छोड़ते दिखाई दे रहे ट्रंप, सात में से छह राज्यों की पसंद बने पूर्व राष्ट्रपति

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। इसके लिए मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ी टक्कर है। इस बीच सामने आए एक ओपिनियन पोल ने चौंकाने वाला दावा किया है। बताया जा रहा कि बाइडन सात में से छह राज्यों में अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी ट्रंप से पीछे चल रहे हैं।

वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा कराए गए सर्वे में पता चला है कि मतदाता बड़ी संख्या में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को लेकर संतुष्ट नहीं हैं। इसके अलावा, यहां के लोगों को बाइडन की क्षमता पर भी संदेह हैं। डोनाल्ड ट्रंप छह राज्यों पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, एरिजोना, जॉर्जिया, नेवाडा और नॉर्थ कैरोलिना में दो से आठ प्रतिशत अंकों से आगे चल रहे हैं। हालांकि, विस्कॉन्सिन में बाइडन तीन अंक आगे चल रहे हैं।

इतना ही नहीं सर्वे में सामने आया है कि हर राज्य में राष्ट्रपति बाइडन के काम को पसंद नहीं करने वाले ज्यादा लोग हैं। वहीं, इसके उलट ट्रंप जब राष्ट्रपति थे तब उन्हें केवल एक राज्य एरिजोना में पसंद नहीं किया जाता था। रियल क्लियर पॉलिटिक्स के अनुसार, ट्रंप और बाइडन के बीच कड़ी टक्कर है। प्रमुख राष्ट्रीय सर्वेक्षणों के औसत से पता चलता है कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप बाइडन से 0.8 प्रतिशत अंक आगे हैं।

एक अखबार का कहना है, बाइडन और ट्रंप दोनों पिछले महीने आसानी से अपनी पार्टी के संभावित उम्मीदवार बन गए थे, लेकिन प्रत्येक उम्मीदवार को 2020 के मुकाबले में एक लंबे और कठिन अभियान का सामना करना पड़ेगा।

इससे पहले, ओहायो के डायटन में एक रैली को संबोधित करते हुए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, हम सीमा पार आने वाली हर कार पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाने जा रहे हैं और अगर मैं चुना जाता हूं तो आप उसे बेच नहीं पाएंगे। अगर अब मैं चुना नहीं जाता हूं तो यहां खून-खराबा होगा। कम से कम यह होगा ही। खून-खराबा देश के लिए होने जा रहा है।

हालांकि, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप के इस बयान का क्या आशय था। दरअसल, जिस समय उन्होंने यह चेतावनी दी उस सनय वह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति वाहन उद्योग के बारे में शिकायत कर रहे थे। एक रिपोर्ट के अनुसार, भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर वह फिर से चुने जाते हैं तो चीन अमेरिका में आयातित किसी भी वाहन को बेचने में सक्षम नहीं होगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रचार अभियान के प्रवक्ता जेम्स सिंगर ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान की निंदा की थी।

हम पाकिस्तान में भी मानवाधिकारों को सुरक्षित देखना चाहते हैं: यूएस

न्यूयार्क, एजेंसी। अमेरिका से गुरुवार को पूछा गया कि वह अरविंद केजरीवाल के मामले में बयान देता है, लेकिन पाकिस्तान में विपक्ष के जेल होने पर कुछ क्यों नहीं बोलता? इसके जवाब में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि दोनों देशों के प्रति हमारे रवैये में कोई अंतर नहीं है।

एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मिलर ने कहा, हम ऐसा नहीं मानते। हम पाकिस्तान में हर किसी के साथ कानून के मुताबिक व्यवहार होते देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वहां भी मानवाधिकार सुरक्षित रहे।

दरअसल, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान लंबे समय से जेल में हैं। उन्हें लेकर अमेरिका चुप रहता है। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को श्वष्ठ ने गिरफ्तार किया। इसे लेकर अमेरिका ने कहा कि वो निष्पक्ष, पारदर्शी, समय पर कानूनी प्रक्रिया का मांग करता है। 25 मार्च को अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर

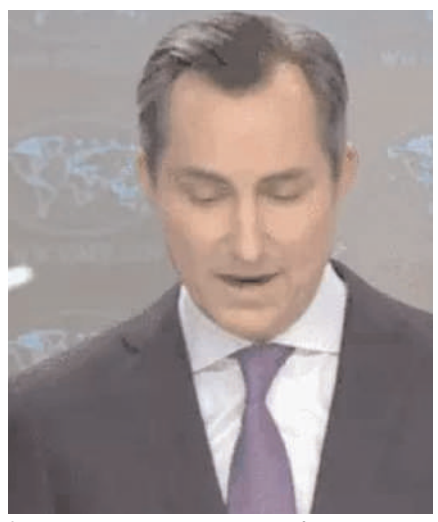

ने कहा था- हमारी सरकार केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले पर नजर बनाए हुए है। हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में कानूनी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होगी। इस दौरान कानून और लोकतंत्र के मूल्यों का पालन किया जाएगा। जर्मनी ने भी कहा था- लोकतंत्र के उसूलों का पालन किया जाए 23 मार्च को जर्मनी ने कहा था, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हमें उम्मीद है कि यहां न्यायालय आजाद है। केजरीवाल के मामले में भी लोकतंत्र के उसूलों का पालन किया जाएगा। केजरीवाल को बिना रुकावट कानूनी मदद मिलेगी। जब तक दोष साबित न हो तब तक किसी भी शख्स को निर्दोष मानने के कानूनी सिद्धांत का पालन होना चाहिए।

जर्मनी के बयान पर भारत ने उनकी ऐंबैसी के डिप्टी हेड को तलब किया था। कहा था, जर्मनी भारत के आतंरिक मामलों में दखलंदाजी न करे। हम इस तरह के बयानों को हमारी न्यायिक प्रक्रिया में दखल मानते हैं, इस तरह के बयान हमारे न्यायालय की निष्पक्षता और आजादी पर सवाल खड़े करते हैं। भारत एक ताकतवर लोकतंत्र है, जहां कानून का पालन होता है। दूसरे मामलों की तरह इस मामले (केजरीवाल की गिरफ्तारी) में भी कानून के तहत कार्रवाई होगी। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका के बयान के एक दिन बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी डिप्लोमैट ग्लोरिया बर्बेना को तलब किया था। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के बयान का विरोध भी किया। कहा, भारत में कानूनी कार्रवाई पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान गलत है। कूटनीति में उम्मीद की जाती है कि देश एक-दूसरे के आंतरिक मसलों और संप्रभुता का सम्मान करेंगे।शराब नीति मामले में हुई केजरीवाल की गिरफ्तारी

शराब नीति मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था। वे 28 मार्च तक श्वष्ठ की हिरासत में हैं। केजरीवाल श्वष्ठ कस्टडी से सरकार चला रहे हैं। उन्होंने कोर्ट में पेशी के समय कहा था कि वे इस्तीफा नहीं देंगे और जरूरत पड़ी तो जेल से सरकार चलाएंगे।

मालदीव से भारतीय सैनिकों की दूसरा बैच इसी महीने निकलेगा, राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने कहा- 10 मई तक पूरी हो जाएगी प्रक्रिया

माले , एजेंसी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने कहा कि दूसरे विमानन मंच पर तैनात भारतीय सैन्यकर्मियों की इसी महीने वापसी हो जाएगी। उन्होंने दोहराया कि यह प्रक्रिया 10 मई तक पूरी हो जाएगी। मुइज्जू का बयान मालदीव में तैनात लगभग 25 भारतीय सैन्यकर्मियों के पहले बैच की वापसी के तीन सप्ताह बाद आया है। राष्ट्रपति ने कहा कि समझौतों के अनुरूप भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी प्रक्रिया पहले से चल रही है। दूसरे प्लेटफार्म पर तैनात सैनिकों को इस महीने के भीतर हटा लिया जाएगा, जबकि तीसरे प्लेटफार्म पर तैनात सैनिकों को 10 मई तक हटा लिया जाएगा। दोनों पक्षों के बीच दो फरवरी को नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद भारत 10 मई तक मालदीव में तीन विमानन प्लेटफार्मों का संचालन करने वाले अपने सैन्य कर्मियों को बदलने पर सहमत हुआ था। पहले बैच ने 10 मार्च से पहले मालदीव छोड़ दिया था। मालदीव में 88 भारतीय सैन्यकर्मी दो हेलीकाप्टर और एक डोर्नियर विमान का संचालन कर रहे थे। वे यहां मानवीय और चिकित्सा निकासी सेवाएं प्रदान कर रहे थे।

स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रकः- देवेन्द्र मालवीय द्वारा श्री सिंध्दी विनायक प्रिंटर्स 26 बी देशबंधु परिसर प्रेस काम्प्लेक्स झोन 1 एम पी नगर भोपाल म.प्र. से मुद्रित एवं 773 / 19 मेघदूत नगर इंदौर म.प्र. से प्रकाशित सम्पादक डॉ. देवेन्द्र मालवीय

कार्यालय पताः- 435 ऑर्बिट मॉल विजय नगर, इंदौर मध्यप्रदेश मोः- 98276-22204 सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र इंदौर रहेगा।

दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त सूचनाए, विचार,आलेख विभिन्न समाचार के स्त्रोत एवं संकलन लेखकों के व संकलनकर्ता के स्वंय जिनका संकलन विभिन्न एजेंसियों, के माध्यम से किया गया है, अतः समस्त प्रकार के प्रकाशन हेतु संपादक, प्रकाशक, मुद्रक का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहमत होना अनिवार्य नहीं है।